रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 27, 1978/ज्येष्ठ 6, 1900
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 27, 1978/JYAISTHA 6, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 1 मई, 1978

का०आ० 1491.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग उड़ीसा सरकार के परामर्श से श्री भूपिन्दर सिंह के स्थान पर श्री लक्ष्मीधर मिश्र, श्रम आयुक्त को उनके इस पद पर कार्यभार संभालने की तारीख से अगले आदेशों तक उड़ीसा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा नामनिर्देशित करता है।

[सं० 154/उड़ीसा/78]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 1st May, 1978

S.O. 1491.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Orissa, hereby nominates Shri Laxmidhar Mishra, Labour Commissioner as the Chief Electoral Officer for the State of Orissa with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Shri Bhupinder Singh.

[No. 154/OR/78]

नई दिल्ली, 4 मई, 1978

का०आ० 1492.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से श्री कैलाश नाथ गोयल के स्थान पर श्री आर०सी० देव शर्मा, न्यायिक सचिव और विधि परामर्शदाता को उनके द्वारा कार्यभार संभालने की तारीख से अगले आदेशों तक उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा नामनिर्देशित करता है।

[सं० 154/उ०प्र०/78]
वी नाग सुब्रमण्यन, सचिव

New Delhi, the 4th May, 1978

S.O. 1492.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Uttar Pradesh, hereby nominates Shri R. C. Deo Sharma, Judicial Secretary and Legal Remembrancer as the Chief Electoral Officer for the State of Uttar Pradesh with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Shri Kailash Nath Goyal.

[No. 154/UP/78]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(न्याय विभाग)

(सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय)

नई दिल्ली, 12 मई, 1978

नोटिस

का० आ० 1493.—इसके द्वारा, लेख्य प्रमाणक नियम (नोटेरीज रूल्स), 1956 के नियम 6 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्राधिकारी को श्री मुरलीधर राव नाईक, एडवोकेट, निवासी घर नं० 4-242, मकटमपुरा, गुलबरगा ने उक्त नियमों के नियम 4 के अधीन, गुलबरगा जिला और गुलबरगा नगर में लेख्य प्रमाणक (नोटेरी) का काम करने की नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र भेजा है ।

उक्त व्यक्ति की लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति के बारे में यदि कोई आपत्तियां हों तो वे इस नोटिस के प्रकाशित होने के चौदह दिन के अन्दर नीचे हस्ताक्षर करने वाले को लिख कर भेज दिये जाये ।

[सं० 22/26/78-न्याय]

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

New Delhi, the 12th May, 1978

NOTICE

S.O. 1493.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Murlidhar Rao Naik, Advocate, Resident of House No. 4-242, Maktampura, Gulbarga for appointment as a Notary to practise in Gulbarga District and Gulbarga city.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 22/26/78-JUS]

नोटिस

का० आ० 1494.—इसके द्वारा, लेख्य प्रमाणक नियम (नोटरीज रूल्स), 1956 के नियम 6 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्राधिकारी को श्री किशोरीलाल कपूर, एडवोकेट, 516, चर्च गेट चेम्बर्स, 5 न्यू मैरीन लेन, मुम्बई ने उक्त नियमों के नियम 4 के अधीन, ग्रेटर मुंबई में लेख्य प्रमाणक (नोटेरी) का काम करने की नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र भेजा है ।

2. उक्त व्यक्ति की लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति के बारे में यदि कोई आपत्ति हो तो वे इस नोटिस के प्रकाशित होने के चौदह दिन के अन्दर नीचे हस्ताक्षर करने वाले को लिख कर भेज दिये जायें ।

[संख्या 22/29/78-न्याय]

ल० द० हिन्दी, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

S.O. 1494.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Kishorilal Kapoor, Advocate, 516, Church Gate Chambers, 5, New Marine Lines, Bombay-20, for appointment as a Notary to practise in Greater Bombay.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. 22/29/78-Jus.]

L. D. HINDI, Competent Authority

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 9 मई, 1978

का० आ० 1495.—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में निम्नलिखित विभागों को जिनके कर्मचारी वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

1. वाणिज्य विभाग
2. ग्राम विकास विभाग
3. सूचना और प्रसारण मंत्रालय
4. वित्त मंत्रालय (रक्षा प्रभाग)

[सं० 12022/1/78-रा० भा० (ख-2)]

हरि बाबू कंसल, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

New Delhi, the 9th May, 1978

S.O. 1495.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following Departments, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

1. Department of Commerce.
2. Department of Rural Development.
3. Ministry of Information and Broadcasting.
4. Ministry of Finance (Defence Division).

[No. 12022/1/78/O. L. (B. 2)]

H. B. KANSAL, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1978

आय-कर

का०आ० 1496.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को निदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (2क) के प्रयोजनों के लिए नीचे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुमोदित किया है ।

1 वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम का नाम :	चयन और संकरण द्वारा सोलेनम खासियनम और अन्य किस्मों का विकास । सोलेनम बेरी का, विभिन्न प्रवर्ग (स्ट्रेन) का मात्रा और गुण के आधार पर मूल्यांकन ।
	श्रेष्ठ प्रवर्ग (एलीट स्ट्रेन) की पहचान और चयन और उस अधिक उपज देने वाली किस्म की मार्गदर्शी पैमाने (पायलट स्केल) पर खेती ।
	बड़े पैमाने पर खेती के प्रयोजनों के लिए बेहतर किस्म के बीजों के उत्पादन के लिए पश्चात्वर्ती विकास ; और

	सोलेमन खासियानम की खेती के लिए मानक पद्धतियों की स्थापना ।
2. प्रायोजक :	मैसर्स आर्गनान (इण्डिया) लिमिटेड, 38 चौरंगी रोड, कलकत्ता-700071।
3. प्रायोजन स्थान.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर
4. आरम्भ की प्रस्तावित तारीख :	1 सितम्बर, 1977
5. पूर्ण होने की अनुमानित तारीख :	30 अगस्त, 1982
6. अनुमानित व्यय :	1,00,000 रु० (एक लाख रुपया)

कृषि विज्ञान, विश्वविद्यालय, बंगलौर को वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 1426 (फा० सं० 203/77/76-आई टी ए-II) तारीख 6 अगस्त, 1976 के द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (i) (ii) के अधीन अनुमोदित किया गया है।

[सं० 2101 (फा०सं० 203/6/77-आई टी ए-II]

जे० पी० शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NEW DELHI, the 4th January, 1978

INCOME-TAX

S.O. 1496.—It is hereby notified for general informatio that the following scientific research programme has been approved for the period specified below for the purposes of sub-section (2A) of section 35 of the Income-tax Act, 1961, by the Director, Department of Science & Techonology, New Delhi.

1. Name of the Scientific Research Programme:	Improvement of Solanum Khasianum and other varieties by selection and hybridisation. Quantitative and Qualitativ of evaluation ofd ifferent strains of Solanum berries. Identification and selection of elite strains and experimental cultivation of this high yielding variety in pilot scale. Subsequent development for the production of better varieties of seeds for the purpose of wide scale cultivavation; and Establishment of standard set of practices for cultivation Solanum Khasianum.
2. Sponsored by :	M/s. Organon (India) Ltd., 38, Chowringhee Road, Calcutta-700071.
3. To be undertaken by :	University of Agricultural Sciences, Bangalore.
4. Proposed date of Commencement.	1st Sept., 1977.
5. Anticipated date of completion. :	30th August, 1982.
6. Estimated Expenditure :	Rs. 1,00,000 (Rs. One lakh).

The University of Agricultural Sciences, Bangalore, has been approved u/s. 35 (1) (ii) of the Income-tax Act, 1961 vide Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No.1426 (F. No. 203/77/76-ITA.II) dated 6th August, 1976.

[No. 2101 (F. No.203/6/77-ITA.II)]

J. P. Sharma, Director

नई दिल्ली, 20 मई, 1978

का० आ० 1497.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 13 मार्च, 1978 की अधिसूचना सं० 6/स्टाम्प/का० स० 33/3/78 वि० क० (का० आ० सं० 794) को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा स्टाम्प शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में सम्परिवर्तन के लिए, विनिमय की दर उसके स्तम्भ (3) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों में विहित करती है।

सारणी

क्रम सं०	विदेशी मुद्रा	100 रु० के समतुल्य विदेशी मुद्रा के विनिमय की दर
1	2	3
1.	आस्ट्रियन शिलिंग	169
2.	आस्ट्रेलियन डालर	10.23
3.	बैल्जियम फ्रेंक	365
4.	कनाडियन डालर	13.20
5.	डेनिश क्रोनर	64.70
6.	डुचो मार्क	23.70
7.	डच गिल्डर	25.30
8.	फ्रेंच फ्रैंक	53.70
9.	हांग कांग डालर	54.40
10.	इटालियन लीरा	9940
11.	जापानी येन	2590
12.	मलयेशियन डालर	27.80
13.	नार्वेजियन क्रोनर	61.80
14.	पौंड स्टर्लिंग	6.3190
15.	स्वीडिश क्रोनर	53.60
16.	स्विस फ्रैंक	22.10
17.	अमरीकी डालर	11.72

[सं० 10/स्टाम्प-का०सं० 33/3/78-वि० क०]

एस० डी० रामस्वामी, अवर सचिव

New Delhi, the 20th May, 1978

S.O. **1497.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) and in supersession of the notification of Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 6/Stamps F. No. 33/3/78-ST (S.O. No. 794) dated the 13th March, 1978, the Central Government hereby prescribe in column (3) of the Table below the rate of exchange for the conversion of the foreign currency specified in the corresponding entry

in column (2) thereof into the currency of India for the purpose of calculating stamp duty.

TABLE

Sl. No.	Foreign currency	Rate of exchange of foreign currency equivalent to Rs. 100
(1)	(2)	(3)
1.	Austrian Schillings	169
2.	Australian Dollars	10.23
3.	Belgian Francs	365
4.	Canadian Dollars	13.20
5.	Danish Kroners	64.70
6.	Deutsche Marks	23.70
7.	Dutch Guilders	25.30
8.	French Francs	53.70
9.	Hong Kong Dollars	54.40
10.	Italian Lire	9940
11.	Japanese Yen	2590
12.	Malaysian Dollars	27.80
13.	Norwegian Kroners	61.80
14.	Pound Sterling	6.3190
15.	Swedish Kroners	53.60
16.	Swiss Francs	22.10
17.	U.S.A. Dollars	11.72

[No. 10/Stamps-F.No. 33/3/78-ST]

S. D. RAMASWAMY, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1978

आय-कर

का०आ० 1498.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर नियम, 1962 के नियम 6(ii) के साथ पठित आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन के प्रवर्ग के अधीन चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है—

(1) यह कि संस्था चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त रकम का एक पृथक लेखा रखेगी।

(2) यह कि संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यकलाप की एक वार्षिक विवरणी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 मई तक परिषद् को ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो अधिकथित किए जाएं और इस प्रयोजन के लिए उसे सूचित किए जाएं।

संस्था

आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ फिजिकल, मेडिकल एण्ड रिहैबिलिटेशन सोसाइटी फार प्रमोशन आफ मेडिकल रिसर्च, मुम्बई

यह अधिसूचना 20-12-77 से 19-12-1979 तक की दो वर्ष कि अवधि तक प्रवृत्त रहेगी।

[सं० 2179 (फा सं० 203/15/78-आई० टी० ए० II]

New Delhi, the 21st February, 1978

INCOME TAX

S.O. 1498.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Medical Research, the prescribed authority for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961, read with rule 6(ii) of the Income-tax Rules, 1962 under the category of "Scientific Research Association" in the field of Medical Research, subject to the following conditions :—

(1) That the institution will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of medical research.

(2) That the institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the Council for each financial year by 15th May, each year at the latest, in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.

INSTITUTION

All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation Society for promotion of Medical Research, Bombay.

This notification is effective for a period of two years from 20-12-1977 to 19-12-1979.

[No. 2179(F. No. 203/15/78-ITA.II)]

आय-कर

का०आ० 1499.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर नियम, 1962 के नियम 6 (ii) के साथ पठित आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन के प्रवर्ग के अधीन चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र मे निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है—

(1) यह कि संस्था चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए प्राप्त रकम का एक पृथक लेखा रखेगी।

(2) यह कि संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यकलाप की एक वार्षिक विवरणी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 मई तक परिषद् को ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो अधिकथित किए जाएं और इस प्रयोजन के लिए उसे सूचित किए जाएं।

संस्था

अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट, पुणे

यह अधिसूचना 21-12-1977 से 20-12-1979 तक की दो वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रहेगी।

[सं० 2180 (फा० सं० 203/14/78-आई० टी० ए० II)]

INCOME TAX

S.O. 1499.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Medical Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the income-tax Act, 1961, read with rule 6(ii) of the Income-tax Rules, 1962 under the category of "Scientific Research Association" in the field of Medical Research subject to the following conditions :—

(1) That the institution will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of medical research.

(2) That the institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the Council for each financial year by 15tht May each year at the

latest, in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.

INSTITUTION

"Ayodhya" Charitable Trust, Pune.

This notification is effective for a period of two years from 21-12-1977 to 20-12-1979.

[No 2180(F. No. 203/14/78-ITA.II)]

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1978

आय-कर

का० आ० 1500.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के के नियम 6(ii) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन के प्रवर्ग के अधीन चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है —

(1) यह कि संस्था चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त रकम का एक पृथक लेखा रखेगी।

(2) यह कि संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यकलाप की एक वार्षिक विवरणी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 मई तक परिषद को ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो अधिकथित किए जाए और इस प्रयोजन के लिए उसे सूचित किए जाए।

संस्था

डायबिटीज रिसर्च सेन्टर, मद्रास।

यह अधिसूचना 21-2-1978 से 20-2-1980 तक की दो वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रहेगी।

[सं० 2187 फा० स 203/13/78-आई टी ए II]

पी० एन० झिगन, अवर सचिव

New Delhi, the 25th February, 1978

INCOME TAX

S.O. 1500.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Medical Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, read with rule 6(ii) of the Income-tax Rules, 1962 under the category of "Scientific research association" in the field of medical research, subject to the following conditions :—

(1) That the institution will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of medical research.

(2) That the institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the Council for each financial year by 15th May each year at the latest, in such form as may be laid down and intimated to them for this purpose.

INSTITUTION

Diabetes Research Centre, Madras.

This notification is effective for a period of two years from 21-2-1978 to 20-2-1980.

[No. 2187 (F. No. 203/13/78-ITA. II)]

P. N. JHINGON, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1978

आय-कर

का०आ० 1501.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना सं० 679 (फा०सं 187/2/74-आ०क० (ए० 1), तारीख 20 जुलाई, 1974 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

क्रम सं० 2, आन्ध्रप्रदेश-I, के सामने, स्तम्भ 3 के नीचे निम्नलिखित जोड़ा जाएगा।

20 नलगोंडा सर्किल (प्रधान कार्यालय, हैदराबाद)।

क्रम संख्या 2ख, आन्ध्र प्रदेश-3, के सामने, स्तम्भ 3 के नीचे निम्नलिखित जोड़ा जाएगा।

16. ओंगोले सर्किल (प्रधान कार्यालय, बापतला)।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1978 से प्रभावी होगी।

[सं० 2229/फा० सं० 189/31क/77-आ० क० (ए 1)]

एम० शास्त्री, अवर सचिव

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 23rd March, 1978

INCOME-TAX

S.O. 1501.—In eexrcise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the Schedule appended to its notification No. 679 F. No. 187/2/74-IT(AI) dated 20-7-1974 as amended from time to time.

Against Sl. No. 2, Andhra Pradesh-I, the following shall be added under Col. 3.

20. Nalgonda Circle (Hqrs. at Hydcrabad).

Against Sl. No. 2B, Andhra Pradesh-III, the following shall be added under Col. 3.

16. Ongole Circle (Hqrs. at Bapatla).

This notification shall take effect from 1-4-1978.

[No. 2229/F. No. 189/31A/77-II(AI)]

M. SHASTRI, Under Secy.

उत्पाद शुल्क समाहर्ता का कार्यालय, मद्रास

मद्रास, 8 मई, 1978

सीमा-शुल्क

का० आ० 1502.—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उप खण्ड (अ) खण्ड 152 के अन्तर्गत भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा), नई दिल्ली से जारी की गयी अधिसूचना संख्या 79/सीमाशुल्क VII तारीख 18 जुलाई 1975 के अधिकारों का प्रयोग करते हुए, उत्पाद शुल्क समाहर्ता मद्रास जो वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग में, अधिसूचना 37 सीमा शुल्क दिनांक 1, फरवरी, 1963 के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता के कार्यालय के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत 'सीमा शुल्क समाहर्ता' भी नियुक्त हैं, तमिलनाडु राज्य के नाते आरकाड जिले के अरकोणम

तालुक के 'अम्मूनूर ग्राम' को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के खण्ड 9 के अन्तर्गत (1962 का 52) 'भाण्डागार स्टेशन' घोषित करते हैं।

[सं० सी० नं० VIII/40/2/78 सीमाशुल्क नीति]

ए० जे० राव, समाहर्ता

THE MADRAS CENTRAL EXCISE COLLECTORATE, MADRAS

Madras, the 8th May, 1978

CUSTOMS

S.O. 1502.—In exercise of the powers conferred by notification No. 79/Customs VII dated 18-7-1975 issued by the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Revenue and Insurance) New Delhi under clause (a) of Section 152 of the Customs Act, 1962, the Collector of Central Excise, Madras also appointed as "Collector of Customs" within the jurisdiction of the Madras Central Excise Collectorate by Government of India. Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 37 Customs dated the 1st February, 1963 hereby declares "AMMANUR" Village in the Arkonam Taluk, North Arcot District, Tamil Nadu State to be a warehousing station under Section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[C. No. VIII/40/78-Cus. Pol.]

I. J. RAO, Collector

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 9 मई, 1978

का० आ० 1503.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार निम्नलिखित फर्मों को 1977-78 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के लेखापरीक्षक के रूप में फिर नियुक्त करती है।

1. मेसर्स रघुनाथ राय एण्ड कम्पनी चार्टर्ड अकाउन्टेंट 3 हनुमान रोड, नयी दिल्ली-110001.
2. मेसर्स सुन्दरम एण्ड श्रीनिवासन चार्टर्ड अकाउन्टेंट, 161, माउन्ट रोड, मद्रास-2.
3. मेसर्स के० एस० अय्यर एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड अकाउन्टेंट, 49, अपोलो स्ट्रीट, बम्बई-23.
4. मेसर्स के० एन० गुटगुटिया, एण्ड कम्पनी चार्टर्ड अकाउन्टेंट, 10/2 हंगर फोर्ड स्ट्रीट, कलकत्ता-700017.

[सं० एफ० 1(2)78/अकाउन्ट]

एन० बालसुब्रह्मण्यन, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 9th May, 1978

S.O. 1503.—In exercise of the powers conferred by section 50 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Govt. hereby reappoint the following firms of Chartered Accountants as Auditors of the Reserve Bank of India for the year 1977-78, namely :—

1. M/s Raghunath Rai & Co., Chartered Accountants, 3, Hanuman Road, New Delhi-110001.
2. M/s. Sundaram & Srinivasan, Chartered Accountants, 161, Mount Road, Madras-2.
3. M/s. K. S. Aiyer & Co., Chartered Accountants, 49, Apollo Street, Bombay-23.
4. M/s. K. N. Gutgutia & Co., Chartered Accountants, 10/2, Hungerford Street, Calcutta-17.

[No. 1(2)/78/Accts.]

N. BALASUBRAMANIAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मई, 1978

का० आ० 1504.—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (1) और खण्ड (ग) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त उप-खण्डों और खण्डों के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित संस्था को अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

सिक्किम इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एण्ड इन्वैस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

[संख्या एफ० 11-13/78-आई० एफ०-II]

विजय शुंगलु, निदेशक

New Delhi, the 10th May, 1978

S.O. 1504.—In pursuance of sub-clause (i) of clause (a) and clause (c) of sub-section (1) of section 9 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964), the Central Government hereby notifies the following institution for the purposes of the said sub-clause and clause namely :

Sikkim Industrial Development and Investment Corporation Limited.

[F. No. 11-13/78-IF. II]

V. K. SHUNGLU, Director

नई दिल्ली, 11 मई, 1978

शुद्धि-पत्र

का०आ० 1505.—भारत के राजपत्र भाग I खण्ड 3(ii) दिनांक 3 सितम्बर, 1977 में क्रमांक 2730 के अन्तर्गत दिनांक 16 अगस्त, 1977 की प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० 8,3/77-स०सी० के हिन्दी पाठ में टंकण की अशुद्धि रह गयी थी जो निम्न प्रकार शुद्ध की जाती है :

पृष्ठ 3003 स्तम्भ II, पंक्ति 5 में शब्द तथा अंक, "27 मार्च 1976" के स्थान पर "27 मार्च, 1975" पढ़ा जाय।

[सं० एफ० 8-3/77-स०सी]

महावीर प्रसाद वर्मा, अवर सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 मई, 1978

का० आ० 1506. भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए संचायक बैटरियों को निर्यात से पूर्व क्वालिटी और निरीक्षण के अधीन करने के लिए कतिपय प्रस्ताव निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, भाग-2 खंड-3 उप-खंड (ii) सं० का० आ० 1302, तारीख 7 मई, 1977 में प्रकाशित किए गए थे और उन सभी व्यक्तियों से जिनका उनसे प्रभावित होना संभाव्य था, राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर आक्षेप तथा सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 10 मई, 1977 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ;

अतः, अब, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् अपनी यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है,

(1) अधिसूचित करती है कि संचायक बैटरियां निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगी ;

(2) संचायक बैटरी निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1978 के अनुसार निरीक्षण के प्रकार को क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जो ऐसी संचायक बैटरियों पर निर्यात से पूर्व लागू होगा ;

(3) भारतीय मानक संस्थान या विदेश के राष्ट्रीय मानकों द्वारा जारी किए गए विनिर्देशों को संचायक बैटरियों के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देती है

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान, ऐसी संचायक बैटरियों के निर्यात का तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित अभिकरणों में से किसी एक द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि संचायक बैटरियों का परेषण क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से संबंधित शर्तों को पूरा करता है तथा निर्यात-योग्य है।

2. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को संचायक बैटरियों के वास्तविक नमूनों के भूमि, वायु या समुद्र मार्ग द्वारा निर्यात पर लागू नहीं होंगी।

3. इस आदेश में संचायक बैटरी से सैलों के समूह (अर्थात् एनोड, कथौड तथा अपघट्य) को समाविष्ट करते हुए वह विद्युत रसायन योजना, अभिप्रेत है जिससे ऐसी प्रतिक्रिया द्वारा जो मूल रूपेण परिवर्तनीय है रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है।

[सं० 6(23)/76-नि० नी० तथा नि० उ०]

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 27th May, 1978

S.O. 1506.—Whereas for the development of the export trade of India certain proposals for subjecting Storage Batteries to quality control and inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule II of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 in the Gazette of India, Part-II. Section 3, sub-section (ii). No. S. O. 1302, in the Gazette dated the 7th May, 1977 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within 45 days from the date of publication of the order in the Official Gazette ;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on 10th May, 1977 ;

And whereas objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, being of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby ;

(1) notifies the Storage Batteries shall be subject to quality control and inspection prior to export ;

(2) specifies the type of inspection in accordance with the Export of Storage Batteries (Quality Control and Inspectoral) Rules, 1978 as the type of quality control and inspection which shall be applied to such Storage Batteries prior to export ;

(3) recognises the specifications issued by the Indian Standards Institution or National Standards of foreign country for Storage Batteries as the standard specifications ;

(4) prohibits the export in the course of international trade of such Storage Batteries unless the same is accompanied by a certificate issued by any of the agencies established under Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), to the effect that the consignment of Storage Batteries satisfies the conditions relating to its quality control and inspection is exportworthy.

2. Nothing in this order shall apply to the export by land, sea or air of bonafide samples of Storage Batteries to prospective buyers.

3. In this Order Storage Battery shall mean an electro-chemical device comprising an array of cells (that is to say, anode, cathode and electrolyte) capable of converting chemical energy into electrical energy by reactions which are essentially reversible.

[No. 6(23)/76-EI & EP]

का० आ० 1507.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संचायक बैटरी निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(ग) 'अधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है ;

(ख) 'अभिकरण' से अधिनियम की धारा 7 के अधीन, कोचीन, मद्रास, कलकत्ता, मुम्बई और दिल्ली में स्थापित अभिकरणों में से कोई एक अभिकरण अभिप्रेत है :

(ग) 'संचायक बैटरी से सैलों के समूह (अर्थात् एनोड, कैथोड तथा अपघट्य) को समाविष्ट करते हुए वह विद्युत रसायन योजना अभिप्रेत है जिससे ऐसी प्रक्रिया द्वारा जो मूल रूपेण परिवर्तनीय है, रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है।

3. क्वालिटी नियंत्रण :—(1) निर्यात के लिए आशयित संचायक बैटरियों की क्वालिटी विनिर्माता द्वारा इससे उपाबंध अनुसूची में दिए गए नियंत्रण के स्तरों सहित विनिर्माण के विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित नियंत्रणों का प्रयोग करके सुनिश्चित की जाएगी, अर्थात् :—

(1) क्रय की गई सामग्री तथा घटकों का नियंत्रण :

(क) प्रयोग की जाने वाली सामग्री या घटकों के गुणधर्मों का समाविष्ट करते हुए क्रय विनिर्देश विनिर्माता द्वारा अधिकथित किए जाएंगे तथा वहां आने वाले लाटों की अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण या परख के लिए पर्याप्त साधन होंगे।

(ख) स्वीकृत परेषणों के साथ क्रय विनिर्देशों की अपेक्षाओं की पुष्टि करते हुए या तो प्रदायकर्ता का परख या निरीक्षण प्रमाण-पत्र होगा, उस दशा मे क्रेता द्वारा कालिक जाच (अर्थात् एक वर्ष में हर तीन मास में एक बार उसी माल की उसी प्रदाय-कर्ता के लिए) पूर्वोक्त परख या निरीक्षण प्रमाण-पत्रों की शुद्धता सत्यापित करने के लिए विशिष्ट प्रदाय-कर्ता के लिए की जाएगी, या क्रय की गई सामग्री या घटकों का या तो कारखाने की प्रयोगशाला में या किसी अन्य प्रयोगशाला या परीक्षण गृह मे नियमित रूप से निरीक्षण या परख की जाएगी।

(ग) किए जाने वाले निरीक्षण या परख के लिए नमूना लेना लेखबद्ध अन्वेषण पर आधारित होगा।

(घ) निरीक्षण या परख किए जाने के पश्चात् स्वीकृत तथा अस्वीकृत सामग्री या घटकों के पृथक्करण के लिए तथा अस्वीकृत माल या घटकों के निपटान के लिए व्यवस्थित पद्धतियां अपनाई जाएंगी।

(ङ) उपरोक्त नियंत्रणों के संबंध में विनिर्माता द्वारा अभिलेख नियमित तथा व्यवस्थित ढग से रखे जाएगें।

(ii) प्रक्रिया नियंत्रण :

(क) विनिर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए विनिर्माता द्वारा विस्तृत प्रक्रिया विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे।

(ख) प्रक्रिया विनिर्देश में अधिकथित की गई प्रक्रियाओं के नियंत्रण के लिए उपस्कर, उपकरण या सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में होंगी।

(ग) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त नियंत्रणो के सत्यापन को सुलभ बनाने के लिए विनिर्माता द्वारा पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे।

(iii) उत्पाद नियंत्रण :

(क) विनिर्माता के पास अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत मान्य विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद की परख करने के लिए या तो स्वयं अपनी परख सुविधाएं होगी या यदि अन्यत्र ऐसी परख सुविधाएं हों तो वहां तक उसकी पहुंच होगी।

(ख) परख के लिए नमूने का लिया जाना (जहा कहीं उपेक्षित हो) लेखबद्ध अन्वेषण पर आधारित होगा।

(ग) विनिर्माता द्वारा किए गए परीक्षण के संबंध में पर्याप्त अभिलेख व्यवस्थित तथा नियमित रूप से रखे जाएंगे।

(iv) परिरक्षण नियंत्रण :

(क) विनिर्माता द्वारा उत्पाद को मौसम के प्रतिकूल प्रभावो से सुरक्षित रखने के लिए विस्तृत विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे।

(ख) भंडारकरण तथा अभिवहन, दोनो के दौरान, उत्पाद अच्छी तरह से परिरक्षित किया जाएगा।

(v) मौसम संबंधी नियंत्रण :

उत्पादन तथा निरीक्षण में प्रयुक्त प्रमापों और उपकरणो की कालिक जांच या अंशशोधन किया जाएगा तथा विनिर्माता द्वारा वृत्तकार्ड के रूप में अभिलेख रखे जाएगे।

(vi) पैकिंग नियंत्रण :

विनिर्माता निर्यात किए जाने वाले पैकजों के लिए विस्तृत पैकिंग विनिर्देश अधिकथित करेगा और उनका कठोरता से पालन करेगा।

(2) निरीक्षण—निर्यात के लिए आशयित संचायक बैटरियो का निरीक्षण इस दृष्टि से किया जाएगा कि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नियंत्रण का समंजन रूपों पर समाधान पद रीति से प्रयोग किया गया है और संचायक बैटरिया उनका लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप हैं।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया—(1)(i) निर्यातकर्ता किसी भी अभिकरण को लिखित रूप में सूचना देगा और ऐसी सूचना के साथ एक घोषणा-पत्र भी देगा कि संचायक बैटरियो के परेषण का विनिर्माण नियम 3 में निर्दिष्ट नियंत्रणो के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण उपायों का प्रयोग करके किया गया है या किया जा रहा है और परेषण इस प्रयोजन के लिए मान्य विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है।

(ii) निर्यातकर्ता उसी समय ऐसी सूचना की एक प्रति परिषद् के निकटतम कार्यालय को देगा।

(iii) परिषद् के पते निम्न हैं :—

प्रधान कार्यालय

निर्यात निरीक्षण परिषद्,
14/1-बी, एजरा स्ट्रीट, (8वी मंजिल)
कलकत्ता-1

क्षेत्रीय कार्यालय

(i) निर्यात निरीक्षण परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, 'अमन चैम्बर्स', (5वीं मंजिल)
113 महर्षि कर्वे रोड,
मुम्बई-4

(ii) निर्यात निरीक्षण परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, मनोहर बिल्डिंग,
महात्मा गांधी रोड, एर्नाकुलम,
कोचीन-11

(iii) निर्यात निरीक्षण परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, म्युनिसिपल मार्केट बिल्डिंग,
3, सरस्वती मार्ग, करौल बाग,
नई दिल्ली-5

(2) निर्यात-कर्ता अभिकरण को परेषण पर लगाए जाने वाले पहचान चिन्ह भी देगा।

(3) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना तथा घोषणा अभिकरण के कार्यालय में विनिर्माता के परिसर से या निर्यात-कर्ता के परिसर से परेषण के भेजे जाने से कम से कम पांच दिन पहले पहुंच जाएगी।

(4) उप-नियम (1) के अधीन सूचना तथा घोषणा प्राप्त होने पर, अभिकरण,—

(क) ऐसे निर्यात-कर्ता की दशा में जो स्वयं विनिर्माता है, उसके यह समाधान कर लेने पर कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान उसने नियम 3 में यथा उपबंधित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का तथा उनको लागू मानक विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद का विनिर्माण करने में इस संबंध में परिषद् द्वारा जारी किए गए निदेशों का यदि कोई हों, प्रयोग किया है,

(ख) ऐसे निर्यात-कर्ता की दशा में जो स्वयं विनिर्माता नहीं है, उसके यह समाधान कर लेने पर कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान विनिर्माता ने नियम 3 में यथा उपबंधित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण तथा उनको लागू मानक विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद का विनिर्माण करने में इस संबंध में परिषद् द्वारा जारी किए गए निर्देशों का, यदि कोई हो, प्रयोग किया है,

निरीक्षण करने के तीन दिन के भीतर यह घोषणा करते हुए प्रमाण-पत्र देगा कि संचायक बैटरियों का परेषण निर्यात-योग्य है :
परन्तु यदि अभिकरण का इस प्रकार का समाधान नहीं होता

है तो वह तीन दिन की उक्त अवधि के भीतर ऐसा प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर देगा तथा ऐसे इंकार की सूचना उसके लिए कारणों सहित निर्यात-कर्ता को देगा ।

5. मान्य चिन्ह का चिपकाया जाना तथा उसके लिए प्रक्रिया—भारतीय मानक संस्था (प्रमाण चिन्ह) अधिनियम, 1952 (1952 का 36), भारतीय मानक संस्था (प्रमाण चिन्ह) नियम, 1955 तथा भारतीय मानक संस्था (प्रमाण चिन्ह) विनियम, 1955 के उपबंध, जहां तक हो सके, निर्यात से पूर्व संचायक बैटरियों पर मान्य चिन्ह चिपकाए जाने या मोहर लगाए जाने की प्रक्रिया के संबंध में लागू होंगे तथा इस प्रकार चिन्हित संचायक बैटरियां नियम 4 के अधीन किसी निरीक्षण के अधीन नहीं होंगी ।

6. निरीक्षण का स्थान—प्रत्येक निरीक्षण, विनिर्माता या निर्यात-कर्ता के परिसर पर या पोतलदान पत्तन पर किया जाएगा।

7 निरीक्षण फीस—नियम 4 के अधीन संचायक बैटरियों के ऐसे प्रत्येक परीक्षण के लिए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रत्येक एक सौ रुपए के लिए तीस पैसे की दर से फीस निर्यात-कर्ता द्वारा अभिकरण को दी जाएगी। यह फीस कम से कम पचास रुपए होगी ।

8. अपील—(1) नियम 4 के उप-नियम (4) के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र देने के इंकार से किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात व्यक्तियों के विशेषज्ञों के पैनल को उसके द्वारा ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने से दस दिन के भीतर अपील कर सकेगा ।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य अशासकीय व्यक्ति होंगे ।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन की होगी ।

(4) अपील प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर निपटाई जाएगी ।

अनुसूची

[नियम 3 (1) देखिए]

नियंत्रण के स्तर

क्रम सं०	परख या निरीक्षण विशेषताएं	अपेक्षाएं	परख या निरीक्षण किए जाने वाले नमूनों की संख्या	लॉट आकार
1	2	3	4	5
1.	डिब्बे तथा ढक्कन	मानक विनिर्देशों के अनुसार	प्रत्येक घटक	
2.	मोहरबंद करने के मिश्रण	-यथोक्त-	पर्याप्त मात्रा	कारखाने में प्राप्त प्रदाय का प्रत्येक बैच
3.	विद्युत अपघट्य	-यथोक्त-	-यथोक्त-	बैटरियों के चिपकाने, बनाने, भरने और चार्ज करने के लिए कारखाने
4.	कार्यकौशल तथा फिनिश			
	(क) घटक	—यथोक्त—	लेखबद्ध अन्वेषण के आधार पर यथा नियत	प्रत्येक लॉट
	(ख) संमजित बैटरी	—यथोक्त—	प्रत्येक	
5.	भंडारकरण के लिए परख	—यथोक्त—	1 नं०	ऐसी बैटरियों के लिए जिनमें एक ही प्रकार की प्लेट्स तथा विभाजक हर छह मास
6.	वायु दाब परख	—यथोक्त—	प्रत्येक सैल	प्रत्येक बैटरी
7.	संक्षिप्त परिपथ परख	—यथोक्त—	—वही—	—यथोक्त—
8.	निम्नलिखित परख के लिए :—			
	(क) क्षमता	—यथोक्त—	(1) 2 नं०	यदि उत्पादन उसी प्रकार के लिए 2 सप्ताह तक लगातार चलता है ।
			(2) 4 नं०	उसी प्रकार के उत्पादन के 3 से 6 सप्ताह के बीच ।
			(3) 2 नं०	यदि 6 सप्ताह से अधिक हो तो उसी प्रकार का हर 3 सप्ताह का उत्पादन ।
	(ख) सामान्य तापमान पर उच्च विसर्जन कार्य	मानक विनिर्देशों के अनुसार	(1) 2 नं०	यदि उत्पादन उसी प्रकार के लिए 2 सप्ताह तक लगातार चलता है ।
			(2) 2 नं०	उस प्रकार के उत्पादन के लिए 3 से 6 सप्ताह के बीच ।
			(3) 2 नं०	यदि 6 सप्ताह से अधिक हो तो उसी प्रकार का हर 3 सप्ताह का उत्पादन ।

1	2	3	4	5
*9.	परख प्रकार			
	(क) चार्ज का अवरोध	—यथोक्त—	प्रत्येक प्रकार की प्लेट तथा विभाजकों का 2 सं०	वर्ष में एक बार
	(ख) अधिक चार्ज करने का प्रतिरोध	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—
	(ग) वाट घटा तथा एक्सियर घंटा क्षमता परख	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—
	(घ) जीवन चक्र परख	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—
10.	न बिखरने की क्षमता के लिए परख तथा उड़ान परख जहां लागू हो।	—यथोक्त—	2 सं०	क्षेत्र की अपेक्षानुसार

*संक्षरण तथा छोटी कैप लैम्प की छोटी बैटरियों 9(घ) के लिए दो वर्ष में एक बार होगी तथा अन्य परखें शामिल नहीं होगी।

[सं० 6(23)/76-नि० नि० तथा नि० उ०]

S.O. 1507.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called Export of Storage Batteries (Quality Control and Inspection) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) ;

(b) "agency" means any one of the agencies established at Cochin, Madras, Calcutta, Bombay and Delhi under Section 7 of the Act.

(c) "Storage Battery" means an electrochemical device comprising an array of Cells (that is to say anode, cathode and electrolyte) capable of converting chemical energy into electrical energy by reactions which are essentially reversible.

3. Quality Control.—(1) The quality of the Storage Batteries intended for export shall be ensured by the manufacturer by effecting the following controls at different stages of manufacture together with the levels of control as given in the Schedule annexed hereto, namely :—

(I) Bought-out materials and components control :—

(a) Purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of materials or components to be used and shall have adequate means of inspection or testing to ensure conformity of the incoming lots.

(b) The accepted consignments shall be either accompanied by a supplier's test or inspection certificate corroborating the requirements of the purchase specification, in which case occasional checks (that is to say once in each quarter of the year for the same supplier of the same material) shall be conducted by the purchaser for a particular supplier to verify the correctness of the aforesaid test on inspection certificates, or the purchase materials or components shall be regularly inspected or tested either in a laboratory in the factory or in some other laboratory or test house.

(c) The sampling for inspection or test to be carried out shall be based on a recorded investigation.

(d) After the inspection or test is carried out, systematic methods shall be adopted in segregating the accepted and rejected materials or components and in disposal of rejected materials or components.

(e) Adequate records in respect of the above mentioned controls shall be regularly and systematically maintained by the manufacturer.

(II) Process Control :—

(a) Detailed process specification shall be laid down by the manufacturer for different processes of manufacture.

(b) Equipments, instrumentation and facilities shall be adequate to control the process as laid down in the process specification.

(c) Adequate records shall be maintained by the manufacturer to ensure the possibility of verifying the controls exercised during the process of manufacture.

(III) Product Control :

(a) The manufacturer shall have either his own adequate testing facilities or shall have access to such testing facilities existing elsewhere to test the product as per the specifications recognised under Section 6 of the Act,

(b) Sampling (wherever required) for testing shall be based on a recorded investigation.

(c) Adequate records in respect of tests carried out shall be regularly and systematically maintained by the manufacturer.

(IV) Preservation Control :—

(a) A detailed specification shall be laid down by the manufacturer to safeguard the product from adverse effects of weather condition.

(b) The product shall be well preserved both during storage and during transit.

(V) Meteorological Control :

Gauzes and instruments used in the production and inspection shall be periodically checked or calibrated and records shall be maintained by the manufacturer in the form of history cards.

(VI) Packing Control :

The manufacturer shall lay down a detailed packing specification for export packages and would strictly adhere to the same.

(2) Inspection—The inspection of Storage Batteries intended for export shall be carried out with a view to seeing that the controls referred to sub-rule (1) have been exercised at the relevant levels satisfactorily and that the Storage Batteries conform to the standard specifications applicable to it.

4. Procedure of inspection.—(1) (i) The exporter shall give intimation in writing to any agency and submit along with such intimation a declaration that the consignment of

Storage Batteries has been or is being manufactured by exercising quality control measures as per controls referred to in rule 3 and that the consignment conforms to the requirements of the specifications recognised for the purpose.

(ii) The exporter shall at the same time endorse a copy of such intimation to the nearest office of the Council.

(iii) The addresses of the Council are as under :

Head Office

Export Inspection Council,
14/1B, Ezra Street (7th Floor),
Calcutta-1.

Regional Offices

(i) Export Inspection Council,
Regional Office,
'Aman Chambers' (4th floor),
113, Maharshi Karve Road,
Bombay-4.

(ii) Export Inspection Council,
Regional Office,
Manohar Buildings,
M. G. Road,
Ernakulam.
Cochin-11.

(iii) Export Inspection Council,
Regional Office,
Municipal Market Building,
3, Saraswati Marg,
Karol Bagh,
New Delhi-5.

(2) The exporter shall also furnish to the agency the identification marks applied on the consignment.

(3) Every intimation and declaration under sub-rule (1) shall reach the office of the agency not less than five days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises or exporter's premises.

(4) On receipt of the intimation and declaration under sub-rule (1) the agency shall,—

(a) in the case of an exporter who himself is the manufacturer, on satisfying itself that during the process of manufacture he had exercised adequate quality control as provided under rule 3 and the instructions, if any, issued by the Export Inspection Council in this regard to manufacture the product according to the standard specifications applicable to it,

(b) in the case of an exporter who is not himself the manufacturer, on satisfying itself that during the process of manufacture the manufacturer had exercised adequate quality control as provided under rule 3 and the instructions, if any, issued by the Council in this regard to manufacture the product according to the standard specifications applicable to it,

(c) within three days of carrying out the inspection, issue a certificate declaring the consignment of Storage Batteries as exportworthy :

Provided that where the agency is not so satisfied, it shall within the said period of three days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor.

5. Affixation of recognised mark and procedure thereof.—The provisions of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 (36 of 1952), the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 and the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations 1955, shall, so far as may be, apply in relation to the procedure of affixation of the recognised mark or seal on Storage Batteries prior to export and Storage Batteries so marked shall not be subjected to any inspection under rule 4.

6 Place of inspection.—Every inspection shall be carried out at the premises of the manufacturer or exporter or at the port of shipment.

7. Inspection fee.—A fee at the rate of thirty paise for every hundred rupees of f.o.b. value subject to a minimum of rupees fifty only for each such consignment of Storage Batteries shall be paid by the exporter to the agency as fee for inspection under rule 4.

8. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (4) of rule 4, may, within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than three but not more than even persons appointed for the purpose by the Central Government.

(2) At least two-thirds of the total membership of the panel of experts shall consist of non-officials.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt.

THE SCHEDULE

[See rule 3(11)]

Levels of control

Sl. No.	Test or inspection Characteristics	Requirements	No. of samples to be tested or inspected	Lot size
1	2	3	4	5
1.	Container and Lid	As per standard specification.	Each component.	
2.	Sealing Compound	-do-	Adequate quantity	Each batch of supply received in the factory.
3.	Electrolyte	-do-	-do-	Each batch of supply received in the factory for pasting, formulation filling and charging of batteries.

1	2	3	4	5
4.	Workmanship and Finish			
	(a) Components	-do-	As fixed on the basis of recorded investigation.	Each lot
	(b) Assembled Battery	-do-	Each	
5.	Storage test	-do-	1 no.	Every six months for batteries having same type of plates and separators.
6.	Air pressure test	-do-	Each Cell	Each battery
7.	Short circuit test	-do-	-do-	-do-
8.	Test for :			
	(a) Capacity	-do-	(i) 2 nos.	If the production is continuous for 2 week for same type.
			(ii) 4 nos.	Between 3 to 6 weeks of production of same type.
			(iii) 2 nos.	Every 3 weeks production of same type if more than 6 weeks.
	(b) High Rate Discharge performance at Normal temperature	As per standard specification	(i) 2 nos.	If the production is continuous for 2 weeks for same type
			(ii) 2 nos.	Between 3 to 6 weeks of production of same type.
			(iii) 2 nos.	Every 3 weeks production of same type if more than 6 weeks.
*9.	Type Tests			
	(a) Retention of charge	-do-	2 nos. of each type of plate & separators.	Once a year.
	(b) Resistance to over charge	-do-	-do-	-do-
	(c) Watt hour and ampere hour efficiency test . . .	-do-	-do-	-do-
	(d) Life cycle tests	-do-	-do-	-do-
10.	Test for unspillability and flight test wherever applicable .	-do-	1 no.	As required by the buyer.

*For Traction and Miner's Cap Lamp Batteries 9(d) will be once in 2 years and other tests are not involved.

[No. 6(23)76-EI&EP.]

आदेश

का०आ० 1508.—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए सफाई तथा जल फिटिंग निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन करने के लिए कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश संख्या का०आ० 1272, तारीख 30 अप्रैल, 1977 के अधीन, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3 उप-खंड (ii), तारीख 30 अप्रैल, 1977 में, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना थी, राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगते हुए प्रकाशित किए गए थे :

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 2 मई, 1977 को उपलब्ध करा दी गई थीं :

और जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है :

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् अपनी यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है,—

(1) अधिसूचित करती है कि सफाई और जल फिटिंग निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगी;

(2) सफाई और जल फिटिंग निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1978 के अनुसार निरीक्षण के प्रकार को क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो निर्यात से पूर्व ऐसी सफाई और जल फिटिंग पर लागू होगा ;

(3) सुसंगत भारतीय मानकों को या आयात करने वाले देश के राष्ट्रीय मानकों को ऐसी सफाई तथा जल फिटिंग के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देती है ।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान, सफाई और जल फिटिंगों के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित अभिकरणों में से किसी एक अभिकरण द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि ऐसी सफाई तथा जल फिटिंगों का परेषण क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से संबंधित शर्तों को पूरा करता है तथा निर्यातयोग्य है ।

2. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को भूमि, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा सफाई तथा जल फिटिंगों के वास्तविक नमूनों के निर्यात पर लागू नहीं होगी ।

3. इस आदेश में 'सफाई तथा जल फिटिंग' से जल वितरण तथा सफाई के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त सभी प्रकार के कॉक, नल, बॉल, वाल्व, फुहारे अभिप्रेत हैं जिसमें सभी प्रकार के दीवार मिश्रक तथा स्नानागार की समस्त फिटिंग भी सम्मिलित हैं ।

[सं० 6(32)/76-नि०नि० तथा नि०उ०]

S.O. 1508.—Whereas for the development of the Export Trade of India certain proposals for subjecting Sanitary and Water Fittings to quality control and inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule II of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, in the Gazette of India, Part II Section 3, Sub-section (ii) dated the 30th April, 1977, under the order of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 1272 dated the 30th April, 1977, inviting objections and suggestions within 45 days of the date of publication of the order in the Gazette from all persons likely to be affected thereby;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 2nd May, 1977.

And whereas the objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government after consulting the Export Inspection Council, being of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby—

(1) notifies that Sanitary and Water Fittings shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) specifies the type of inspection in accordance with the Export of Sanitary and Water Fittings (Inspection) Rules, 1978 as the type of quality control and inspection which shall be applied to such sanitary and water fittings prior to export;

(3) recognises the relevant Indian standards or National Standards of the importing country as the standard specifications for such sanitary and water fittings;

(4) prohibits the export in the course of international trade of such sanitary and water fittings, unless the same are accompanied by a certificate issued by any of the agencies established under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) to the effect that the consignment of sanitary and water fitting satisfy the conditions relating to its quality control and inspection and is exportworthy.

2. Nothing in this order shall apply to the export by land, sea or air of bonafide samples of sanitary and water fittings to prospective buyers.

3. In this order, "Sanitary and Water Fittings" shall mean all types of cocks, taps, ball, valves, shower roses including all types of wall mixers and all bath-room fittings used for water supply and sanitation purposes.

[No. 6(32)/76-EI&EP]

का० आ० 1509—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफाई तथा जल फिटिंग निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1978 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'अधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है;

(ख) 'अभिकरण' से अधिनियम की धारा 7 के अधीन कोचीन, मद्रास, कलकत्ता, मुम्बई और दिल्ली में स्थापित अभिकरणों में से कोई अभिकरण अभिप्रेत है;

(ग) 'सफाई तथा जल फिटिंग' से जल वितरण तथा सफाई के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त सभी प्रकार के कॉक, नल, बॉल वाल्व तथा फुहारे अभिप्रेत हैं । जिसमें सभी प्रकार के दीवार मिश्रक तथा स्नानागार की समस्त फिटिंग सम्मिलित है ।

3. निरीक्षण का आधार :—निर्यात के लिए आशयित सफाई तथा जल फिटिंगों का निरीक्षण इस दृष्टि से किया जाएगा कि वह अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य मानक विनिर्देशों अर्थात् ऐसी सफाई तथा जल फिटिंगों के लिए सुसंगत भारतीय मानकों या आयात कर्ता देश के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है ।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :—(1) सफाई तथा जल फिटिंगों का निर्यात करने का इच्छुक निर्यात-कर्ता अपने ऐसा करने के आशय की सूचना लिखित रूप में देगा तथा ऐसी सूचना के साथ ऐसे निर्यात से संबंधित निर्यात संविदा में दिए गए विनिर्देशों की घोषणा किसी भी अभिकरण को देगा ताकि वह नियम 3 के अनुसार निरीक्षण कर सके ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना तथा घोषणा, निर्यात-कर्ता या विनिर्माता के परिसर से भेजे जाने की अनुसूचित तारीख से कम से कम सात दिन पहले दी जाएगी तथा इसके साथ ही सूचना की एक प्रति परिषद् के निम्नलिखित कार्यालय में किसी एक को जो कि निरीक्षण के स्थान के निकटतम हो, भेजी जाएगी, अर्थात् :—

प्रधान कार्यालय	निर्यात निरीक्षण परिषद्, 'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर', 14/1-बी, एजरा स्ट्रीट, कलकत्ता-700001.

क्षेत्रीय कार्यालय . 1. निर्यात निरीक्षण परिषद्,
'अमन चैम्बर्स', 5वी मंजिल,
113, महर्षि कर्वे मार्ग,
बम्बई-400004.

2. निर्यात निरीक्षण परिषद्,
'मनोहर बिल्डिंगस',
महात्मा गांधी मार्ग, एर्नाकुलम,
कोचीन-682011.

3. निर्यात निरीक्षण परिषद्,
'म्युनिसिपल मार्किट बिल्डिंग' (5वीं मंजिल),
3, सरस्वती मार्ग, करोल बाग,
नई दिल्ली-110005.

(3) उप-नियम (1) के अधीन सूचना तथा घोषणा प्राप्त होने पर, अभिकरण नियम 3 तथा इस संबंध में परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों, यदि कोई हों, के अनुसार सफाई तथा जल फिटिंगों का निरीक्षण करेगा ।

(4) (क) निरीक्षण की समाप्ति के पश्चात्, अभिकरण तुरन्त पैकेजो को परेषण में इस ढंग से मुद्रा बन्द करेगा कि यह सुनिश्चित हो सके कि मुद्रा बन्द के साथ छेड़ छाड़ नही की जा सकती है ।

(ख) परेषण की अस्वीकृति की दशा में, यदि निर्यात कर्ता चाहे तो परेषण को अभिकरण द्वारा मुद्राबन्द स्टांपित या स्टेंसिल नही किया जायगा, तथापि ऐसे मामलो में, निर्यात कर्ता अस्वीकृति के विरुद्ध अपील करने का हकदार नही होगा ।

(5) जब अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि सफाई और जल फिटिंगों का परेषण मान्य विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है, तो वह निरीक्षण की समाप्ति के तीन दिन के भीतर निर्यातकर्ता को यह घोषणा करते हुए प्रमाण पत्र देगा कि परेषण निरीक्षण से संबंधित शर्तों को पूरा करता है और निर्यातयोग्य है :

परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार का समाधान नहीं हो जाता वहां वह उक्त तीन दिन की अवधि के भीतर ऐसा प्रमाण पत्र देने से इंकार कर देगा तथा ऐसे इंकार करने की सूचना, उसके कारणों सहित, निर्यातकर्ता को देगा ।

5. निरीक्षण का स्थान.—इन नियमो के प्रयोजन के लिए सफाई और जल फिटिंगो का निरीक्षण—

(क) विनिर्माता के परिसर पर किया जाएगा,

या

(ख) उस परिसर पर किया जायगा जहां निर्यात कर्ता द्वारा सफाई तथा जल फिटिंगों निरीक्षण के लिए प्रस्तुत की जाती है, परन्तु यह तब जब कि वहां निरीक्षण और परख के प्रयोजन के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों ।

6. निरीक्षण फीस:—प्रत्येक परेषण के लिए पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के प्रत्येक एक सौ रुपए पर पचास पैसे की दर से, निरीक्षण फीस न्यूनतम पचास रुपए के अधीन रहते हुए निर्यातकर्ता अभिकरण को दी जाएगी ।

7. अपील:—(1) नियम 4 के उप-नियम (5) के अधीन अभिकरण के प्रमाण-पत्र देने से इंकार करने से व्यथित कोई व्यक्ति उसके द्वारा ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात व्यक्तियों के विशेषज्ञो के पैनल को अपील कर सकेगा ।

(2) पैनल में विशेषज्ञो के पैनल की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो तिहाई सदस्य अशासकीय सदस्य होंगे ।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों की होगी ।

(4) अपील प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर निपटाई जाएगी ।

[सं० 6(32)/76-नि०नि० तथा नि०उ०]

S.O. 1509.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Sanitary and Water Fittings (Inspection) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of the publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "agency" means any of the agencies established at Cochin, Madras, Calcutta, Bombay and Delhi under Section 7 of the Act;

(c) "Sanitary and Water Fittings" means all types of Cocks; taps, ball valves, showers roses including all types of wall-mixers and all bath-room fittings used for water supply and sanitation purposes.

3. Basis of Inspection.—Inspection of Sanitary and Water Fittings intended for export shall be carried out with a view to seeing that the same conform to the standard specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act, namely the relevant Indian Standards or the National Standards of the impodting country for such Sanitary and Water Fittings.

4. Procedure of inspection.—(1) An exporter intending to export Sanitary and Water Fittings shall give intimation in writing of his intention so to do and submit along with such intimation a declaration of the specification stipulated in the export contract relating to such export to any agency to enable it to carry out the inspection in accordance with rule 3.

(2) Every intimation and declaration under sub-rule (1) shall be given not less than seven days before the Scheduled date of despatch from the exporters or manufacturers' premises and copy of the intimation shall simultaneously be endorsed to any of the following of fices of the Council which is nearest to the place of inspection namely :—

Head office : Export Inspection Council

'World Trade Centre',

14/1B, Ezra Street,

Calcutta-700001.

Regional Offices : 1. Export Inspection Council 'Aman Chambers', 4th floor, 113, Maharshi Karve Road, Bombay-400004.

2. Export Inspection Council 'Manohar Buildings', Mahatma Gandhi Road, Ernakulam, Cochin-682011.

3. Export Inspection Council, 'Municipal Market Building', (4th floor), 3, Saraswati Marg, Karol Bagh, New Delhi-110005.

(3) On receipt of the intimation and declaration under sub-rule (1), the agency shall carry out the inspection of Sanitary and Water Fittings in accordance with rule 3 and the instructions, if any, issued by the Council from time to time in this regard.

(4) (a) After completion of the inspection, the agency shall immediately seal the packages in the consignment in a manner as to enusre that the sealed goods cannot be tampered with.

(b) In case of rejection of a consignment, if the exporter so desires, the consignment may not be sealed, stamped or stencilled by the agency and in such cases, however, the exporter shall not be entitled to prefer an appeal against rejection.

(5) When the agency is satisfied that the consignment of Sanitary and Water Fittings complies with the requirements of the recognised specification, it shall issue within three days of completion of inspection a certificate to the exporter declaring that the consignment satisfies the conditions relating to inspection and is export worthy :

Provided that where the agency is not so satisfied it shall within the said period of three days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor.

5. Place of inspection.—Inspection of Sanitary and Water Fittings for the purpose of these rules shall be carried out—

(a) at the premises of the manufacturer.

or

(b) at the premises at which the Sanitary and Water Fittings are offered for inspection by the exporter, provided adequate facilities for the purpose of inspection and testing exist therein.

6. Inspection fee.—Subject to minimum of rupees fifty for each consignment, a fee at the rate of fifty paise for every Rs. 100 of f.o.b. value, shall be paid by the exporter to the agency as inspection fee.

7. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of agency to issue a certificate under sub-rule (5) of rule 4, may within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than three but more than seven persons appointed for the purpose by the Central Government.

(2) The panel shall consist of at least two-thirds of non-official of the total membership of the panel of experts.

(3) The quorum for the panel shall be there.

(4) The appeal shall be disposed of within fifteen days of its receipt.

(No. 6(32)/76-FI&EP)

आदेश

का०आ० 1510:— भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिये निर्यात से पूर्व कीलकों को निरीक्षण के अधीन लाने के लिए कतिपय प्रस्ताव, निर्यात क्वालिटी (नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) के अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश संख्या का०आ० 1551 तारीख 28 मई, 1977 के अधीन भारत के राजपत्र भाग 2, खंड-3, उप-खंड (2) तारीख 28 मई, 1977 में प्रकाशित किए गए थे। और राजपत्र में उस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से 45 दिनो के भीतर, उन सभी व्यक्तियो से आक्षेप तथा सुझाव मांगे गए थे, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 31 मई, 1977 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और जनता से प्राप्त आक्षेपों तथा सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ;

अतः, अब, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् अपनी यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है,

(1) अधिसूचित करती है कि कीलकों का निर्यात से पूर्व निरीक्षण किया जाएगा ;

(2) कीलकों की निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1978 के अनुसार निरीक्षण के प्रकार को निरीक्षण को उस प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो निर्यात से पूर्व ऐसे कीलकों पर लागू होगा।

(3) (क) भारतीय मानकों या विदेश के राष्ट्रीय मानको को ;

(ख) ऐसे विनिर्देशों को, जो ऊपर खंड (क) के अन्तगत नही आते है किन्तु जो ऐसे मानकों की जो निर्यातकर्ता द्वारा कीलकों के लिये सहमत विनिर्देश घोषित किए गए है, परीक्षा तथा अनुमोदन के प्रयोजन के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा नियुक्त विशेषज्ञो के पैनल द्वारा अनुमोदित किए गए हैं:

मान्यता देती है —

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसे कीलको के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित अभिकरणो मे से किसी एक द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र न हों कि ऐसे कीलकों का परेषण निरीक्षण से संबधित शर्तों को पूरा करता है तथा निर्यात योग्य है।

2. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को भूमि मार्ग, जल मार्ग या वायु मार्ग द्वारा कीलको के प्रमाणिक नमूनो के निर्यात पर लागू नही होगी।

3. इस आदेश में 'कीलकों' के अभिप्राय सभी प्रकार की चटखनियां दो नोक वाली कीलें, पेच, कीलक, ढीबरी तथा वाशर है जो कि धातुओ या इनकी मिश्र धातुओ से बनाये गये है और जो दो या अधिक भागों को एक साथ बांधने के लिए प्रयुक्त होते हैं।

[सं० 6(33)76/नि० नि० तथा नि०उ०]

ORDER

S.O. 1510.—Whereas for the development of the Export Trade of India certain proposals for subjecting Fasteners to inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, in the Gazette of India, **Part II**, Section 3, Sub-section (ii) dated the 28th May, 1977, under the order of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 1551, dated the 28th May, 1977 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within 45 days from the date of publication of the Order in the Official Gazette ;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 31st May, 1977;

And whereas the objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, being of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the Export Trade of India, hereby—

(1) notifies that Fasteners shall be subject to inspection prior to export ;

(2) specifies the type of inspection in accordance with the Export of Fasteners (Inspection) Rules, 1978 as the type of inspection which shall be applied to such Fasteners prior to export ;

(3) recognises—

(a) Indian Standards or National Standards of a foreign country,

(b) the specifications which do not fall under clause (a) above but are approved by a Panel of Experts, appointed by the Export Inspection Council for the purpose of examining and approving such standards declared by the exporter as the agreed specifications for Fasteners.

(4) prohibits the export in the course of international trade of such Fasteners unless the same are accompanied by a certificate issued by any of the agencies established under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) to the effect that the consignment of such Fasteners conforms to the conditions relating to inspection and is exportworthy.

2. Nothing in this order shall apply to the export by land, sea or air of bonafide samples of Fasteners to prospective buyers.

3. In this Order, "Fasteners" shall mean all types of bolts, studs, screws, rivets, nuts and washers manufactured from metals or their alloys and used for securing two or more parts together.

[No. 6(33)/76-EI&EP]

का०आ० 1311—केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीलकों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं : इन नियमो मे, जहाँ तक संदर्भ मे अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) 'अधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है

(ख) 'अभिकरण' से अधिनियम की धारा 7 के अधीन मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली तथा मद्रास में स्थापित अभिकरणों में से कोई अभिप्रेत है।

(ग) 'कीलक' से सभी प्रकार की चटखनियाँ, दो नोक वाली कीलें पेच, कीलक डिबरी तथा वाशर, अभिप्रेत वाशर है जो धातुओं या मिश्र धातु में बनाये गये हों तथा दो या अधिक भागों को एक साथ मिलाने के लिये प्रयुक्त होते हैं।

(घ) 'अनुसूची से अभिप्राय इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

3. निरीक्षण का आधार : (1) निर्यात किए जाने वाले कीलकों का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के विचार से किया जायगा कि वह अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त तथा अनुसूची 1 में दिए गए मानक विनिर्देशों के अनुरूप है।

(2) अनुसूची 2 का सारणी के उपबंधों के अनुसार नमूना लिया जाएगा।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया (1) : कीलकों के निर्यात करने की वांछा रखने वाले निर्यातकर्ता अपने ऐसा करने के आशय की सूचना लिखित रूप में देगा तथा ऐसी सूचना के साथ अभिकरण को ऐसे निर्यात से संबंधित निर्यात संविदा में अनुबन्ध विनिर्देशों का घोषणा पत्र देगा ताकि वह नियम 3 के अनुसार निरीक्षण कर सके।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना तथा घोषणा पोत लदान की अनुसूचित तारीख से कम से कम पाँच दिन पहले दी जायगी तथा सूचना की एक प्रति उसी समय परिषद् के कार्यालय में से किसी को जो निरीक्षण के स्थान के पास है, दी जायगी, अर्थात् :—

1	2
मुख्य कार्यालय	निर्यात निरीक्षण परिषद् 14/1-बी, एजरा स्ट्रीट, (आठवीं मंजिल) कलकत्ता—700001
क्षेत्रीय कार्यालय	(1) निर्यात निरीक्षण परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई। अमन चैम्बर्स (पाँचवी मंजिल), 113, महर्षि करवे रोड, मुम्बई—400004
	(2) निर्यात निरीक्षण परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली, म्यूनिसिपल मार्केट बिल्डिंग, सरस्वती मार्ग, करौल बाग, नई दिल्ली—110005
	(3) निर्यात निरीक्षण परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय, कोचीन, मनोहर बिल्डिंग, महात्मा गाँधी रोड, एर्नाकुलम, कोचीन-682011.

(3) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना और घोषणा प्राप्त होने पर, अभिकरण कीलकों का नियम 3 तथा परिषद् द्वारा इस संबंध मे समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों, यदि कोई हो, के अनुसार निरीक्षण करेगा।

(4) (क) निरीक्षण की समाप्ति के पश्चात्, अभिकरण तुरन्त ही पैकेजों को परेषण में इस ढंग से सील बन्द करेगा कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सील किए गए माल के साथ छेड़-छाड़ नही की जा सकती है।

(ख) परेषण की अस्वीकृति की दिशा मे, यदि निर्यातकर्ता की ऐसी इच्छा हो तो परेषण को अभिकरण द्वारा सील नही किया जायगा, तथापि ऐसी दशाओं में, निर्यातकर्ता अस्वीकृति के विरुद्ध अपील करने का हकदार नही होगा।

(5) जहाँ अभिकरण का समाधान हो गया है कि कीलकों का परेषण मान्यताप्राप्त विनिर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करता है, वहाँ वह निरीक्षण की समाप्ति के 3 कार्य दिवसों के भीतर निर्यातकर्ता को यह घोषणा करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा कि परेषण निरीक्षण से संबंधित शर्तों को पूरा करता है तथा निर्यात योग्य है।

परन्तु जहाँ अभिकरण का इस प्रकार का समाधान नही हुआ है वहाँ वह उक्त तीन दिनों की अवधि के भीतर ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने से इकार कर देगा तथा ऐसे इकार की सूचना उसके कारणों सहित निर्यातकर्ता को देगा।

5. निरीक्षण का स्थान : (क) विनिर्माता के परिसर पर किया जाएगा।

(ख) उस परिसर पर किया जायगा जहाँ निर्यातकर्ता द्वारा कीलको के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया है परन्तु यह तब जब कि वहाँ निरीक्षण तथा परीक्षण करने के प्रयोजनार्थ पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों।

6. निरीक्षण फीस : प्रत्येक परेषण के लिये पचास रुपये की सीमा के भीतर रहे हुए, पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रत्येक एक सौ रुपये पर

पचास पैसे की दर से निरीक्षण फीस नियमों के अधीन निर्यातकर्ता द्वारा अभिकरण को दी जायगी।

7. अपील : (1) नियम 4 के उप-नियम (5) के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाण पत्र देने से इंकार से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कम से कम तीन या अधिक से अधिक सात व्यक्तियों के विशेषज्ञों के पैनल को अपील कर सकेगा।

(2) विशेषज्ञों के पैनल के कुल सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई गैर-सरकारी सदस्य होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन की होगी।

(4) अपील का निपटारा प्राप्त होने के दस दिन के भीतर किया जाएगा।

अनुसूची-1

[नियम 3(1) देखिए]

कीलकों के लिए विनिर्देश

(क) विदेश के भारतीय मानकों या राष्ट्रीय मानकों,

अथवा

(ख) कीलकों के लिए निर्यात-कर्ता द्वारा सहमत विनिर्देशों के रूप में घोषित विनिर्देश जो ऊपर खंड (क) के अन्तर्गत नहीं आते हैं किन्तु ऐसे मानकों की परीक्षा तथा अनुमोदन के प्रयोजन के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल द्वारा अनुमोदित किए गए हों।

अनुसूची 2

[नियम 3(2) देखिए]

नमूना सारणी तथा अनुरूपता के लिए मापदण्ड

सारणी संख्या-1

(एम० एस० कीलकों से भिन्न)

लोट आकार (एक प्रकार तथा आकार)	बिना विध्वंसक दोषों की परख के लिए नमूना आकार	अनुमोदन संख्या
150 तक	5	0
151 से 500	20	1
501 से 1000	32	2
1001 से 3000	50	3
3001 से 10,000	80	5
10,001 तथा अधिक	125	7

सारणी संख्या 2

(केवल एम० एस० कीलकों के लिए)

लॉट आकार (एक प्रकार तथा आकार)	बिना विध्वंसक दोषों की परख के लिए नमूना आकार	अनुमोदित संख्या
150 तक	8	1
151 से 500	20	3
501 से 1000	32	5
1001 से 3000	50	7
3001 से 10,000	80	10
10,000 तथा अधिक	125	14

सारणी संख्या 3

(सभी प्रकार के कीलकों के लिए)

लॉट आकार (एक प्रकार तथा आकार)	विध्वंसक दोषों की परख के लिए नमूना आकार	अनुमोदित संख्या
800 तक	1	शून्य
801 से 8000	2	शून्य
8001 से 22,000	3	शून्य
22,001 तथा अधिक	5	शून्य

[सं० 6(33)/76-नि०नि० तथा नि०उ०]

सी० बी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक

S.O. 1511.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Export of Fasteners (Inspection) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires ;

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) ;

(b) "agency" means any of the agencies established at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Act ;

(c) "Fasteners" means all types of bolts, studs, screws, rivets, nuts and washers manufactured from metals or their alloys and used for securing two or more parts together.

(d) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

3. Basis of Inspection.—(1) Inspection of Fasteners intended for export shall be carried out with a view to seeing that the same conform to the Standard specifications recognised by the Central Government under Section 6 of the Act and given in Schedule I.

(2) Sampling shall be done in accordance with the provisions of the Table of Schedule II.

4. Procedure of Inspection.—(1) An exporter intending to export Fasteners shall give intimation in writing of his intention so to do and submit along with such intimation a declaration of the specifications stipulated in the export contract relating to such export to any of the agencies to enable it to carry out the inspection in accordance with rule 3.

(2) Every intimation and declaration under sub-rule (1) shall be given not less than five days before the scheduled date of shipment and a copy of the intimation shall simultaneously be endorsed to any of the following offices of the Council, which is nearest to the place of inspection, namely :—

Head office.—Export Inspection Council, 14|1B, Ezra Street (7th Floor), Calcutta-700001.

Regional Offices.—(1) Export Inspection Council, Regional Office : Bombay, Aman Chambers, (4th Floor), 113, M. Karve Road, Bombay-400004.

(2) Export Inspection Council, Regional Office : Delhi, Municipal Market Building, 3, Saraswati Marg, Karol Bagh, New Delhi-110005.

(3) Export Inspection Council, Regional Office : Cochin, Manohar Buildings, Mahatma Gandhi Road, Ernakulam, Cochin-682011.

(3) On receipt of the intimation and declaration under sub-rule (1), the agency shall carry out the inspection of Fasteners in accordance with rule 3 and the instructions, if any, issued by the Council from time to time in this regard.

(4) (a) After completion of the inspection, the agency shall immediately seal the packages in the consignment in a manner so as to ensure that the sealed goods cannot be tampered with.

(b) In case of rejection of a consignment, if the exporter so desires, the consignment may not be sealed by the agency and in such cases, however, the exporter shall not be entitled to prefer an appeal against the rejection.

(5) When the agency is satisfied that the consignment of Fastoners complies with the requirements of the recognised specifications, it shall issue within three working days of completion of inspection, a certificate to the exporter declaring that the consignment satisfied the conditions relating to inspection and is exportworthy.

Provided that where the agency is not so satisfied, it shall, within the said period of three days, refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor.

5. Place of Inspection.—Inspection of Fasteners shall be carried out, (a) at the premises of the manufacturer,

or

(b) at the premises at which the Fasteners are offered for inspection by the exporter, provided adequate facilities for the purpose of inspection and testing exist therein.

6. Inspection Fee.—Subject to a minimum of Rupees fifty for each consignment, a fee at the rate of fifty paise for every Rs. 100 of the f.o.b. value, shall be paid by the exporter to the agency as inspection fee, under these rules.

7. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (5) of rule 4 may within fifteen days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a Panel of Experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by the Central Government.

(2) The Panel shall consist of at least two-thirds of non-officials of the total membership of the Panel of Experts.

(3) The quorum for the Panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within ten days of its receipt.

SCHEDULE I

[See rule 3 (1)]

Specifications for Fasteners.

(a) Indian Standards or National Standards of a foreign country :

or

(b) The specifications which do not fall under clause (a) above but are approved by a Panel of Experts, appointed by the Export Inspection Council for the purpose of examining and approving such standards declared by the exporter as the agreed specification for Fasteners.

SCHEDULE—II

[See rule 3(2)]

Sampling Tables and Criteria for Conformity

Table No. 1

(Other than M.S. Fasteners)

Lot size (One type and size)	Sample size for non-destructive tests	Permissible number of defects
1		
Upto 150	5	0
151 to 500	20	1
501 to 1000	32	2
1001 to 3000	50	3
3001 to 10,000	80	5
10,001 and above	125	7

TABLE No. 2

(M.S. Fasteners only)

Lot size (One type and size)	Sample size for non-destructive test	Permissible number of defects
Upto 150	8	1
151 to 500	20	3
501 to 1000	32	5
1001 to 3000	50	7
3001 to 10,000	80	10
10,001 and above	125	14

TABLE No. 3

(For all types of Fasteners)

Lot size (One type and size)	Sample size for destructive test	Permisible number o defects
1	2	3
Upto 800	1	NIL
801 to 8000	2	NIL
8001 to 22,000	3	NIL
22,001 and above	5	NIL

[No. 6(33)/76 EI& EP]

C. B. KUKRETI, Jt. Director

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1978

का० आ० 1512.—सर्वश्री भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० रानीपुर, हरिद्वार (यू. पी०) को पश्चिमी जर्मनी से वैक्यूम डिगेसिंग उपकरण का आयात करने के लिए 23,64,846.00 रुपए (तेइस लाख चौसठ हजार आठ सौ छियालिस रुपए मात्र) का एक आयात लाइसेंस सं० आई०/सी०जी०/2068975 दिनांक 24-2-1975 प्रदान किया गया था। उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्राविनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह भी बताया गया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति का 22,00,463.87 रु० के लिए आंशिक उपयोग कर लिया गया और उसमें 1,64,382.13 रुपए शेष बचा हुए थे।

2. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने नोटरी हरिद्वार, के सामने विधिवत शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं सन्तुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई है। इसलिए यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उप धारा 9 (सी०सी०) के अन्तर्गत) प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग कर सर्वश्री हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० रानीपुर, हरिद्वार को जारी किए गए आयात ला० सं० आई०/सी०जी०/2068975 दिनांक 24-2-1975 की मूल मुद्रा विनमय नियंत्र प्रयोजन प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

3. लाइसेंस धारी को उपर्युक्त लाइसेंस की एक अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या सी०जी० -11/एच०-1(78)/74-75/160]

Office of the Chief Controller of Imports and Exports

ORDER

New Delhi, the 8th April, 1978

S.O. 1512.—M/s. Bharat Heavy Eectricals Ltd., Ranipur, Hardwar (U.P.) were granted an import licence No. 1/CG/2068976 dated 24-2-1975 for Rs. 23,64,846/- (Rupees Twenty Three Lakh Sixty Four thousand Eight hundred and Forty Six only), for import of Vaoum Degassing Equipment from West Germany. They have applied for the issue of a duplicate Exchange Control Purposes copy of the said licence on the ground that the original Exchange Control Copy has been lost/misplaced. It is further stated that the original Exchange Control Copy was utilised/partly for Rs. 22,00,463.87 and the balance available on it was Rs. 1,64,382.13.

2. In support of this contention, the applicant has filed an affidavit duly sworn in before Notary, Hardwar. I am accordingly satisfied that the original Exchange Control Copy of the said licence has been lost. Therefore, in exercise of the powers conferred under Sub-Clause 9 (cc) of the Imports (Control) Order 1955 dated 7-12-1955 as amended, the said original Exchange Control Purposes Copy of licence No. 1/CG/2068975 dated 24-2-1975 issued to M/s. Bharat Heavy Electricals Ltd., Ranipur, Hardwar is hereby cancelled.

3. A duplicate Exchange Control Purposes Copy of the said licence is being issued separately to the licensee.

[No. CGII/H.I. (76)/74-75/160]

आदेश

का० आ० 1513—सर्वश्री भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लि० झांसी (यू०पी०) को 59,10,069 00 रुपये (उनसठ लाख दस हजार उनहत्तर रुपए मात्र) के लिए एक आयात लाइसेंस सं० आई०/सी०जी०/1416960 दिनांक 2-3-1976 प्रदान किया गया था। बाद में लाइसेंस का मूल्य कम करके 41,10,069.00 रुपए कर दिया गया था। उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह भी बताया गया है कि मूल मुद्रा विनिमय प्रयोजन प्रति स्टे बैंक लि०, कानपुर में पंजीकृत थी और उसका आंशिक उपयोग कर लिया गया था। वह 39,10,069.00 रुपए के लिए उपयोग में लाई गई थी और उसमें बाकी बचा हुआ 2,00,00.00 रुपए था।

2. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने नोटरी झांसी (यू० पी०) के सामने विधिवत शपथ लकर एक शपथपत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि उपयुक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रक प्रयोजन प्रति खो गई है। इसलिए यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उप-धारा 9(सी०सी०) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर सर्वश्री हैवी इलिक्ट्रिकल लि० झांसी (यू० पी०) को जारी किए गए आयात लाइसेंस सं० आई०/सी०जी०/1416960 दिनांक 2-3-1976 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति एतद्वारा रद्द को जाती है।

3. लाइसेंसधारी को उपर्युक्त लाइसेंस की एक अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या सी०जी० 11/एच०-1(7)/75-76/159]

टी० टी० ला, उप मुख्य नियंत्रक

ORDER

S.O. 1513.—M/s. Bharat Heavy Electricals Ltd., Jhansi, (U.P.) were granted an import licence No. 1/CG/1416960 dated 2-3-1976 for Rs. 59,10,069/- (Rupees Fifty Nine lakhs Ten thousands and Sixty Nine only) subsequently the value of the licence has been reduced to Rs. 41,10,069/-. They have applied for the ssue of a duplicate Exchange Control Copy purposes Copy of the said licence on the ground that the original Exchange Control Copy has been lost/misplaced. It is further stated that the original Exchange Control Copy was registered at State Bank Ltd., Kanpur and utilised partly. It was uilised for Rs. 39,10,069/- and the balance available on it was Rs. 2,00,000/-.

2. In support of this contention, the applicant has filed an affidavit duly sworn in before Notary, Jhansi (U.P) I am accordingly satisfied that the original Exchange Control Copy of the said licence has been lost. Therefore, in exercise of the powers conferred under Sub-Clause 9(cc) of the Imports (Control) Order 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Exchange Control Purposes copy of licence No. 1/CG 1416960 dated 2-3-1976 issued to M/s. Bharat Heavy Electricals Ltd, Jhansi (U.P.) is hereby cancelled.

3. A duplicate Exchange Control Purposes copy of the said licence is being issued separately to the licencee.

[No. CGII/H.I. (7)/74 75/160]

T. T. LA. Chief Controller

(भारतीय मानक संस्था)

नई दिल्ली, 1978-05-08

का० आ० 1514.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी एम/एल-5837 जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, 1978-04-01 से रद्द कर दिया गया है । क्योंकि अब इसमें फर्म की रुचि नहीं है ।

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सीएम/एल-5837 1977-01-24	देवी दयाल (सेल्स) प्रा० लि०, गुप्ता मिल्स इस्टेट, रे रोड, बम्बई-400010 (महाराष्ट्र)	क्लोरडेन पायसनीय तेजद्रव	IS : 2682—1966 क्लोरडेन पायसीन तेजद्रव की विशिष्टि

[संख्या सी एम डी/55:5837]

(Indian Standards Institution)

New Delhi, the 1978-05-08

S.O.1514.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L-5837 particulars of which are given below has/have been cancelled with effect from 1978-04-01 as the firm is not interested:

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. and date	Name & Address of the Licensee	Article/Process Covered by the Licensees Cancelled	Relevant Indian Standards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	CM/L-5837 1977-01-24	Devidayal (Sales) Pvt. Ltd., Gupta Mills Estate, Reay Road, Bombay-400010 (Maharashtra).	Chlordane Emulsifiable Concentrates.	IS : 2682—1966 Specification for Chlordane Emulsifiable Concentrates.

[No. CMD/55: 5837]

नई दिल्ली, 1978-05-12

का० आ० 1515.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 5 के उपविनियम (1) के अनुसार अनुसूचित किया जाता है कि जिस भारतीय मानक के ब्यौरे यहां दिए हैं वह रद्द हो गया है और वापस लिया जाए ।

अनुसूची

क्रम संख्या	भारतीय मानक की पद संख्या और शीर्षक	भारतीय मानक के राजपत्र में छपने की तिथि और एसओ संख्या	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 2477—1970 हाथ से घुमाने वाला घूर्णन यंत्र, कंधे पर रखने वाले की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (II) दिनांक 1972-07-08 में प्रकाशित एस ओ 1635 दिनांक 1972-06-13	क्योंकि IS : 2477—1970 में निर्धारित अपेक्षाएं IS : 5135 (भाग 2)—1977 हाथ से घुमाने वाले घूर्णन यंत्र भाग 2 कंधे पर रखने वाला, में सम्मिलित कर दी गई है ।

[संख्या सीएमडी/13 : 7]

New Delhi, the 1978-05-12

S.O.1515 —In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955 as amended from time to time, it is, hereby notified that the Indian Standard (s), particulars of which is mentioned in the Schedule given hereafter, has been cancelled and stands withdrawn:

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Title of the Indian Standard Cancelled	S.O. No. & Date of the Gazette Notification in which Establishment of the Indian Standard was Notified	Remarks
1	2	3	4
1.	IS : 2477—1970 Specification for hand rotary duster, shoulder mounted type (first revision).	S.O. 1635—dated 1972-06-13 published in the Gazette of India, Part II, Section-3, sub-section (ii) dated 1972-07-08.	As the requirements stipulated in IS : 2477-1970 have been included in IS : 5135 (Pt. II)—1977 Specification for hand rotary duster : Part II Shoulder mounted type.

[No. CMD/13 : 7]

का०आ० 1516.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 5 के उपविनियम (1) के अनुसार अनुसूचित किया जाता है कि जिन भारतीय मानको के ब्यौरे अनुसूची में दिए गए है वे रद्द हो गए है उन्हे वापस माना जाए।

अनुसूची

क्रम सं०	भारतीय मानक की सं० और रद्द होने की तिथि	भारतीय मानक के राजपत्र में छपने की तिथि और एस० ओ० सख्या	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 705–1955 शुष्क बैटरी द्वारा चालित कम्यूनिटी रेडियो सेट की विशिष्टि (परीक्षार्थ)	भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनाँक 1955-06-04 में प्रकाशित एस० आर० ओ० सख्या 1172 दिनाँक 1955-05-25	क्योकि IS : 705–1955 के अधीन आने वाले रेडियो सेट जिनमे इलेक्ट्रान ट्यूब काम में आती है और बैटरी पैक से चलते है अब देश में नही बनते ।
2.	IS : 1034–1957 कम्यूनिटी रेडियो सेटो की लाउड-स्पीकर प्रणाली की विशिष्टि	भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनाँक 1957-09-02 मे प्रकाशित एस०आर०ओ० 2909 दिनाँक 1957-09-02	क्योकि IS : 1034–1957 में निर्धारित अपेक्षाएं IS : 7741 (भाग 4)–1977 लाउडस्पीकरों की विशिष्टि भाग 4 कम्यूनिटी रेडियो सेटों के लाउडस्पीकर में सम्मिलित कर दी गई है ।
3.	IS : 1036–1957 6 वोल्ट संचायक चालित समुदाय रेडियो रिसीवरो की विशिष्टि	भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनाँक 1957-06-29 में एस०आर० ओ० 2120 दिनाँक 1957-06-17 के अन्तर्गत प्रकाशित	IS : 1036–1957 के संचायक बैटरियों द्वारा चालित अधीन आने वाले समुदाय रेडियो सेट अब पुराने पड़ गए है ।
4.	IS : 2902–1964 जड़ित कार्बन फिल्म अवरोधक टाइप 1 की विशिष्टि	भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3 में उपखण्ड (ii) दिनाँक 1965-06-26 मे एस०ओ० 2042 दिनाँक 1965-06-10 के अन्तर्गत प्रकाशित	क्योंकि IS : 2902–1964 और IS : 2903-1964 में दी गई सामग्री अब IS : 5786 सिरीज में शामिल कर दी गई है ।
5.	IS : 2903–1964 जड़ित कार्बन फिल्म अवरोधक टाइप 2 की विशिष्टि	भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनाँक 1965-04-10 में एस० ओ० 1152 दिनाँक 1965-04-02 के अन्तर्गत प्रकाशित।	

[सं० सी०एम०डी०/13 . 7]

S.O.1516.—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955 as amended from time to time, it is hereby, notified that the Indian Standard(s), particulars of which are mentioned in the Schedule given hereafter, have been cancelled and stands withdrawn:

SCHEDULE

Sl.	No. & Title of the Indian Standard Cancelled	S.O. No. & Date of the Gazette Notification in which Establishment of the Indian Standard was Notified	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
	IS: 705-1955 Specification for dry battery operated community radio receivers (tentative)	S.R.O. 1172 dated 1955-05-25 published in the Gazette of India, Part II, Section-3, dated 1955-06-04	As the community radio receivers, covered in IS:705—1955, employing electron tubes and operating from battery packs are no longer made in the country.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	IS:1034—1957 Specification for loud-speakers systems for community radio receivers.	S.R.O. 2909 dated 1957-09-02 published in the Gazette of India, Part II, Section-3, dated 1957-09-14.	As the requirements contained in IS : 1034—1957 have been included in IS : 7741 (Pt. IV)—1977 Specification for loudspeakers : Part IV Loud-speakers for community radio receivers.
3.	IS : 1036—1957 Specification for 6-volts accumulator operated community radio receivers.	S.R.O. 2120 dated 1957-06-17 published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, dated 1957-06-29.	As the community radio receivers covered in IS : 1036—1957, which are being operated from accumulator batteries have now become obsolete.
4.	IS : 2902—1964 Specification for fixed carbon film resistor, Type I.	S.O. 2042 dated 1965-06-10 published in the Gazette of India, Part II, Section-3, sub-section (ii) dated 1965-06-26.	As the material covered in IS : 2902 1964 and IS : 2903—1964 have now been covered in IS : 5786—series.
5.	IS : 2903—1964 Specification for fixed carbon film resistors, Type II.	S.O. 1152 dated 1965-04-02 published in the Gazette of India, Part II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1965-04-10.	

[No. CMD/13 : 7]

का०आ० 1517.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (2) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि रसायन प्रतिरोधी मसालो की प्रति इकाई मुहर लगने की फीस अनुसूची मे दिए गए ब्यौरे के अनुसार निर्धारित की गई है यह फीस 1978-01-01 से लागू होगी ।

अनुसूची

क्रम संख्या	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी मानक की संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	रसायन प्रतिरोधी चिनाई के मसाले	(1) IS : 4832 (भाग 1 और 2)—1969 रसायन प्रतिरोधी चिनाई के मसालो की विशिष्टि भाग 1 सिलिकेट वाले और भाग 2 रेजिन वाले (2) IS 4832 (भाग 3)—1968 रसायन प्रतिरोधी चिनाई के मसालो की विशिष्टि भाग 3 गंधक वाले	एक मीटरी टन	रु० 10 00

[स० सी०एम०डी०/13 : 10]

वाई० एस० वेंकटेश्वरन, अपर महानिदेशक

S.O. 1517.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955 the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fee per unit for chemical resistant mortars details of which are given in the Schedule hereto annexed, has been dertermined and the fee(s) shall come into force with effect from 1978-01-01 :

THE SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Chemical resistant mortars.	(i) IS : 4832 (Part I & II)—1969 Specification for chemical resistant mortars : Part I Silicate type and Part II Resin type. (ii) IS : 4832 (Part III)—1968 Specification for chemical resistant mortars : Part III sulphur type.	One Tonne.	Rs. 10 00

[No CMD/13 :10]

Y. S. VENKATESWARAN, Additional Director General.

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 11 मई, 1978

का० आ० 1518—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन सेन्ट्रल इण्डिया कमर्शियल एक्सचेंज लि०, ग्वालियर द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किये गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोक हित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को अलसी की अग्रिम संविदाओं के बारे में 2 जून, 1978 से पहली जून, 1979 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित है) की एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

[मिसिल सं० 12(8)-आई०टी०/78]

वी० श्रीनिवासन, उप-सचिव,

(Department of Civil Supplies & Cooperation)

New Delhi, the 11th May, 1978

S.O. 1518.—Tht Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Central India Commercial Exchange Limited, Gwallor, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of one year from the 2nd June, 1978 to the 1st June, 1979 both days inclusive, in respect of forward contracts in linseed.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such direction as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(8)-IT/78]

V. SRINIVASAN, Dy. Secy

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1978

का० आ० 1519—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा एक मुश्त सौदे या प्रशासनिक तथा वित्तीय प्रबन्ध के अधीन, पंजाब सरकार को हस्तांतरित की गई मुआवजा भंडार की सम्पत्तियों अर्थात् अर्जित निष्क्रांत सम्पत्तियों, कृषि भूमियों, दुकानों, खाली स्थानों के प्रबन्ध, अभिरक्षा तथा निपटान करने के लिए पंजाब सरकार के पुनर्वास विभाग में कार्य कर रहे श्री मनमोहन हुरिया भूमि दावा अधिकारी व सहायक बन्दोबस्त आयुक्त तथा सौनिन्द्र सिंह, बन्दोबस्त अधिकारी (लेखा) व सहायक बन्दोबस्त आयुक्त को उनके अपने कार्यों के अलावा उक्त अधिनियम या उसके द्वारा बन्दोबस्त आयुक्त को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए, पंजाब राज्य में बन्दोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० 1(25)/विशेष सैल/75-एस०एस-II]

वीना नाथ असीजा, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 29th April, 1978

S.O. 1519.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 the Central Government hereby appoints, with immediate effect, Shri Manmohan Hurria, Land Claims Officer-cum-Assistant Settlement Commissioner and Shri Sonindra Singh, Settlement Officer (Accounts)-cum-Assistant Settlement Commissioner in the Rehabilitation Department, Government of Punjab as Settlement Commissioners in the State of Punjab for the purpose of performing in addition to their duties as Land Claims Officer and Settlement Officer (Accounts respectively, the functions assigned to a Settlement Commissoner by or under the said Act in regard to management, custody and disposal of the acquired evacuee properties, agricultural lands, shops, vacant sites, forming part of Compensation Pool situated in the State of Punjab transferred to the State Government of Punjab under "Package Deal" or under administrative and financial arrangements.

[No. 1(25)/Spl. Cell/75-SS.II.]

D. N. ASIJA, Jt. Director

का० आ० 1520—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम 1954 की धारा 34 की उप धारा (2) द्वारा बन्दोबस्त आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह इसके द्वारा पंजाब सरकार के पुनर्वास विभाग में कार्य कर रहे श्री मनमोहन हुरिया भूमि दावा, अधिकारी व सहायक बन्दोबस्त आयुक्त तथा श्री सोनिन्द्र सिंह, बन्दोबस्त अधिकारी (लेखा) व सहायक बन्दोबस्त आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, पंजाब राज्य सरकार को 'एक मुश्त सौदे' या प्रशासनिक तथा वित्तीय व्यवस्था के अधीन पंजाब सरकार को हस्तांतरित की गई मुआवजा भंडार की पंजाब राज्य में स्थित अर्जित निष्क्रांत सम्पत्तियों, कृषि भूमियों, दुकानों, खाली स्थानों के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 23, 24 तथा 28 के अधीन आवश्यक आदेश पारित करने के लिए अपनी शक्तियां सौंपते है।

[सं० 1(25)/विशेष सैल/75-एस० एस०-II]

कौशल कुमार, मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त

S.O. 1520.—In exercise of the powers conferred on the Chief Settlement Commissioner by Sub-Section (2) of Section 34 of the Displaced Persons Compensation & Rehabilitation) Act, 1954, he hereby delegates to Shri Manmohan Hurria, Land Claims Officer-cum-Assistant Settlement Commissioner and Shri Sonindera Singh, Settlement Officer (Accounts)-cum-Assistant Settlement Commissioner, in the Rehabilitation Department of the Punjab Government exercising the powers of Settlement Commissioners, his powers under sections 23, 24 and 28 of the said Act for the purpose of passing necessary orders under these Sections in respect of acquired evacuee properties, agricultural lands, shops, vacant sites forming part of Compensation Pool situated in the State of Punjab transferred to the State Government of Punjab under "Package Deal" or under administrative and financial arrangement.

[No. 1(25)/Spl. Cell/75-SS. II]

KAUSHAL KUMAR, Chief Settlement Commissioner

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 5 मई, 1978

का० आ० 1521—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम

और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 2620 तारीख 28-7-77 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यत. उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संग्रहों से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

डी०एस० सानन्द-1 और डी०एस० सानन्द-33 से जी०जी०एस० पिप पर पाइप लाईन बिछाने हेतु उपयोग के अधिकार का अर्जन

स्टेट : गुजरात	जिला :	मेहसाना	तालुक :	कलोल
गांव	सर्वे सं०	हेक्टेयर	एरिया	सेंटीयर
1	2	3	4	5
नसमेद	558	0	39	60
	385	0	10	95
	389	0	08	40
	390	0	09	00
	कार्ट ट्रैक			
	391	0	01	35
	391	0	18	00
	447	0	03	60
	451	0	97	20
	454	0	14	00
	455	0	01	15
	कार्ट ट्रैक	0	01	35
	464	0	19	65
	462	0	06	90
	488	0	28	95
	487	0	15	60
	486	0	16	58
	254 ब	0	12	38
	253/1	0	04	20
	251	0	05	25
	252	0	15	00
	246	0	13	03
	240	0	04	00
	कार्ट ट्रैक	0	02	70
	40	0	22	80
	41	0	21	30
नसमेद—(जारी)	37	0	16	63
	46	0	18	35
	54	0	07	50
	47	0	21	45
	51	0	17	43
	50	0	11	32
	76	0	15	50
	77	0	02	64
	78	0	08	53
	79	0	17	67
	88 पेकी	0	11	00
	88 पेकी	0	10	46
	88 पेकी	0	20	31

[सं० 12016/4/77-प्रोडक्शन-I]

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 5th May, 1978

S.O. 1521.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 2620 dated 28-7-77 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Acquisition of right of user for laying pipeline from D.S. Sanand-1 & D.S. Sanand-33 to G.G.S. at SIP.

State : Gujarat	District : Mehsana	Taluka : Kalol
Village	Survey No.	Hectare / Are / Centiare
1	2	3 / 4 / 5
Nasmed	558	0 / 39 / 60
	385	0 / 10 / 95
	389	0 / 08 / 40
	390	0 / 09 / 00

1	2	3	4	5
Nasmed—(contd.)	Cart-track	0	01	35
	391	0	18	0
	447	0	03	60
	451	0	97	20
	454	0	14	00
	455	0	01	15
	Cart-track	0	01	35
	464	0	19	65
	462	0	06	90
	488	0	28	95
	487	0	15	60
	486	0	16	58
	254	0	12	38
	253/1	0	04	20
	251	0	05	25
	252	0	15	00
	246	0	13	03
	240	0	04	00
	Cart-track	0	02	70
	40	0	22	80
	41	0	21	30
	37	0	16	63
	46	0	18	35
	54	0	07	50
	37	0	21	45
	51	0	17	43
	50	0	11	32
	76	0	15	50
	77	0	02	64
	78	0	08	53
	79	0	17	67
	88 Palki	0	11	00
	88 Paiki	0	10	46
	88 Paiki	0	20	31

[No. 12016/4/77-Prod.I]

का०आ० 1522—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962(1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ०सं० 2977 तारीख 1-9-77 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों मे उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संयंत्रों से मुक्त रूप मे, घोषणा के प्रकाशन को इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कूप नं ऐस० डी० ऐफ० मे लाइन कनेक्टिंग ऐस० बी० ऐफ० जी० जी० ऐस० —I

राज्य . गुजरात	जिला : मेहसाणा	तालुका : मेहसाणा		
गांव	सर्वेक्षण नं०	हेक्टर	ऐ आर ई	सेन्टीआर
हेबुवा	111	0	03	48
	80	0	08	64
	81	0	03	84

[सं० 12016/4/77-प्रोडक्शन II]

S.O. 1522.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 2977 dated 1-9-77 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances

SCHEDULE

Acquisition of Right of user from well no SD to line Connecting ROV SBF—GGS-I.

State : Gujarat	District : Mehsana	Taluka : Mehsana		
Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Hebuva	111	0	03	48
	80	0	08	64
	81	0	03	84

[No. 12016/4/77—Prod. II]

का० आ० 1523—यत. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 1865 तारीख 20-5-76 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी संपत्तियों से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

रूप सं०—एस० पी० पी० ओ० से एन० के० 54

राज्य-गुजरात

गांव	सर्वेक्षण नं०	हेक्टर	एआरई	सेन्टीयर
चालासण	जिला	महेसाणा	तालुका	कडी
	82	0	03	50
बालसासण	जिला—अमदाबाद	तालुका—विरमगाम		
	255	0	09	75
	254	0	01	80
	257	0	21	73

[सं० 12016/7/76-प्रोडक्शन]

के० पी० जेठानी, अवर सचिव

S.O. 1523.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 1865 dated May, 76 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Acquisition of right of user from SPA to NK—54
State : GUJARAT

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Village : Chalasan	District : Mehsana		Taluka : Kad	
	82	0	03	50
Village : Balsasan	District : Ahmedabad		Taluka : Viramgam	
	255	0	09	75
	254	0	01	80
	257	0	21	75

[No. 12016/7/76-Prod.]

K. P. JETHANI, Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1978

का० आ० 1524.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दीपघर और दीपपोत निदेशक कोचीन को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है और उक्त अधिकारी नौवहन और परिवहन मंत्रालय के, और उसके द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर लिए गए और उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन के सरकारी स्थानों की बाबत, अपनी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

[नि० सं० 24 एम एस (4)77]

एस० रामचन्द्र राव, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 20th April, 1978

S.O. 1524.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the Director of Lighthouses and Lightships, Cochin being Gazetted Officer of Government to be estate officer for the purposes of the said Act, and the said Officer shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on estate officer by or under the said Act, within the limits of his jurisdiction, in respect of the public premises belonging to, and taken on lease by, or on, behalf of the Ministry of Shipping and Transport and which are under his administrative control.

[F. No. 24MS(4)77]

S. RAMACHANDRA RAO, Under Secy.

संस्कृति विभाग

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

(पुरातत्व)

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1978

का० आ० 1525:—चूंकि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इस अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्मारक राष्ट्रीय महत्व का नहीं रह गया है :—

अतः अब केन्द्रीय सरकार प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि पूर्वोक्त स्मारक उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सांस्कृतिक महत्व का नहीं रह गया है।

अनुसूची

राज्य	जिला	स्थान	संस्मारक का नाम	संरक्षण अधिसूचना और उसकी तारीख (i) प्राथमिक (ii) पुष्टकारी (iii) पश्चात्वर्ती, यदि कोई हो
1	2	3	4	5
पंजाब	अमृतसर	अमृतसर	गोविन्दगढ़ किला	(i) सं० 25210 तारीख 17-11-1925। (ii) सं० 13990 तारीख 4-5-1926 पंजाब सरकार। (iii) सं० 818 तारीख 13-4-1927 शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग।

[सं 3/3/77-एम]

म० न० देशपाण्डे, महानिदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF CULTURE

(Archaeological Survey of India)

New Delhi, the 14th March, 1978

(ARCHAEOLOGY)

S.O. 1525.—Whereas the Central Government is of opinion that the ancient and historical monument specified in the schedule to this notification has ceased to be of national importance :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 35 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby declares that the monument aforesaid has ceased to be of national importance for the purposes of the said Act.

SCHEDULE

State	District	Locality	Name of Monument	Protection notification No. & Date (i) Preliminary (ii) Confirmatory (iii) Subsequent, if any
1	2	3	4	5
Punjab	Amritsar	Amritsar	Govindgarh Fort	(i) No. 25210, dated 17-11-1925. (ii) No. 13990, dated 4-5-1926 Govt of Punjab. (iii) No. 818, dated 13-4-1927 Department of Education, Health and Land.

[No.3/3/77-M

M. N. DESHPANDE, Director General and Ex-officio Jt. Secy

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 मई, 1978

का० आ० 1526.—यतः कतिपय उपान्तरण, जिन्हें केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में दिल्ली की बृहत योजना तथा क्षेत्रीय विकास योजना में करने की प्रस्तावना करती है, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के उपबन्धों के अनुसरण में, सूचना सं० एफ० 3(265)/68-एम०पी० दिनांक 11 फरवरी, 1978 के साथ तथा उक्त अधिनियम की धारा 11क की उपधारा (3) में यथापेक्षित प्रकाशित किए गए थे जिसमें उक्त सूचना की तारीख से 30 दिन के अन्दर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित उक्त संशोधन के संबंध में आक्षेपों/सुझावों पर विचार करने के बाद दिल्ली की बृहत योजना तथा क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन करने का निर्णय किया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11(क) की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली की बृहत योजना तथा क्षेत्रीय विकास योजना में, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित उपान्तरण करती है, अर्थात् :—

संशोधन

"मास्टर प्लान/क्षेत्रीय विकास प्लान (जोन डी०-20-डिफेन्स कालोनी) में मनोरंजनात्मक प्रयोग" के लिए उद्दिष्ट भूमि जो उत्तर में रेलवे लाइन, पूर्व में 30.48 मीटर (100 फुट) चौड़ी सड़क (सेवानगर तथा डिफेंस कालोनी के बीच) दक्षिण में एक अन्य सड़क तथा पश्चिम में मनोरंजनात्मक क्षेत्र से घिरी हुई है, उसमें से लगभग 2.39 हैक्टेयर (5.906 एकड़) भूमि का भू उपयोग बदलकर "संस्थानिक प्रयोग" (उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) कर दिया गया है)"

[सं० के०-13011(34)/77-यू० डी० आई० ए०]

हरि राम गोयल, अवर सचिव

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 17th May, 1978

S.O. 1526.—Whereas Certain modification, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi and Zonal Development Plan regarding the areas mentionod hereunder, were published with Notice No. F. 3(265)/68-MP dated the 11th February, 1978 in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions, as required by sub-section (3) of section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice;

And whereas, the Central Government after considering the objections and suggestions with regard to the said modification mentioned hereunder, have decided to modify the Master Plan for Delhi and Zonal Development Plan;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi and Zonal Development Plan with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India, namely :—

MODIFICATION

"The land use of an area measuring about 2.39 hects. (5.906 acres), out of the land earmarked for 'recreational use' in the Master Plan/Zonal Development Plan (Zone D-20—Defence Colony) and surrounded by Railway line in the north, 30.48 metres (100 ft.) wide road in the east, (between Sewa Nagar and Defence Colony), another road in the south and recreational area in the west, is changed to 'Institutional use' (Higher Secondary School)".

[No. K-13011/34/77-UDI(A)]

H. R. GOEL, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 16 मई, 1978

का० आ० 1527.—संख्या 327 दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड iii के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने बस्ती टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-6-78 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-3-/78-पीएचबी]

आर० सी० कटारिया, सहायक महानिदेशक (पी० एच० बी०)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 16th May, 1978

S.O. 1527.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16-6-1978 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Basti Telephone Exchange, U.P. Circle.

[No. 5-3/78-PHB]

R. C. KATARIA, Assistant Director-General (PHB)

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 मई, 1978

का० आ० 1528.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पर्सको, 1/27, प्रिंस गुलाम मोहम्मद रोड, कलकत्ता-26, नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35017 (5)/78-पी० एफ० II]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 9th May, 1978

S.O. 1528.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Pressco, 1/27, Prince Golam Mohammad Road, Calcutta-26, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1977.

[No. S. 35017(5)/78-PF.II]

का० आ० 1529.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स लिबरा एक्सपोर्टर्स लिमिटेड, मार्फत लोहिया जूट प्रेस, 28 बी टी रोड़, कलकत्ता-2, नामक स्थापन से सबम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 मई, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35017 (6)/78-पी० एफ० II(i)]

S.O. 1529.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Libra Exporters Limited, Care Off Lohia Jute Press, 28, B. T. Road, Calcutta-2, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1977.

[No. S. 35017(6)/78-PF-II(i)]

का० आ० 1530.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 मई, 1977 से मैसर्स लिबरा एक्सपोर्टर्स लिमिटेड, मार्फत लोहिया जूट प्रैस, 28 बी० टी० रोड़, कलकत्ता-2 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस० 35017(6)/78-पी० एफ० II(ii)]

S.O. 1530.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of May, 1977, the establishment known as Messrs. Libra Exporters Limited, Care Off Lohia Jute Press, 28, B. T. Road, Calcutta-2, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35017(6)/78-PF-II(ii)]

का० आ० 1531.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एम० बी० मिनरल इण्डस्ट्रीज, मुहम्मद बाजार, बीर भूम, पश्चिम बंगाल, जिसके अन्तर्गत इनका 40, स्ट्रेंड रोड़, तीसरी मंजिल कमरा नं० 2, कलकत्ता-1 स्थित प्रधान कार्यालय भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अगस्त, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35017 (10)/78-पी० एफ० II]

S.O. 1531.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs M. B. Mineral Industries, Mahammad Bazar,, Birbhum, West Bengal, including its Head Office at 40, Strand Road, 2nd Floor Room No. 2, Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1976.

[No. S-35017(10)/78-PF-II]

का० आ० 1532.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ए० के० कारपोरेशन लिमिटेड, 93 पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-16, नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35017 (11)/78 पी० एफ० II(i)]

S.O. 1532.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs A. K. Corporation Limited, 93, Park Street, Calcutta-16 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1977.

[No. S-35017/11/78-PF. II(i)]

का० आ० 1533 केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकिर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 जुलाई, 1975 से मैसर्स ए० के० कारपोरेशन लिमिटेड, 93 पार्क स्ट्रिट, कलकत्ता-16

नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस० 35017 (11)/78-पी० एफ० II(ii)]

S.O. 1533.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of July, 1975 the establishment known as Messrs A. K. Corporation Limited, 93, Park Street, Calcutta-16, for the purposes of the said proviso.

[No. S-35017/11/78-PF. II(ii)]

का० आ० 1534 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री शान्ती प्रेस, 156, तारक प्रमानिक मार्ग, कलकत्ता 6 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 मई 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35017(14)/78 पी० एफ० II]

S.O. 1534.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shri Shanti Press, 156, Tarak Pramanick Road, Calcutta-6 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1976.

[No. S. 35017/14/78-PF. II]

का० आ० 1535 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एम० के० अनुसधान प्रयोगशाला, प्लाट सं० 2, जवाहर कोआपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट लिमिटेड, कामोथ, पनवेल, जिला--कोलाबा, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1974 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35018(9)/78 पी० एफ०II]

S.O. 1535.—Whreas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs M. K. Research Laboratory, Plot No. 2 Jawhar Co-operative Industrial Estate Limited Kamothe, Panvel, District Kolaba, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1974.

[No. 35018(9)/78-PF. II]

का०आ० 1536 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जनरल मेजरमेंट्स एण्ड कंट्रोल्स, प्लाट सं० 1 और 3, जवाहर को-आपरेटिव इण्डस्ट्रियल एस्टेट लिमिटेड, कामोथ, तालुक पनवेल, जिला कोलाबा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952, (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1974 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35018(10)/78पी०एफ-II]

S.O. 1536.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs General Measurements and Controls, Plot No. 1 and 3, Jawahar Co-operative Industrial Estate Limited, Kamothe, Taluk Panvel, District Kolaba, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1974.

[No. S. 35018(10)/78-PF. II]

का०आ० 1537—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डी० के० गियर्स, लेक रोड, भानडुप, मुम्बई-78 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 जुलाई, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35018(12)/78-पी०एफ०-II]

S.O. 1537.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Dee-Kay Gears, Lake Road, Bhandup, Bombay-78, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of July, 1976.

[No. S. 35018(21)/78-PF-II]

का०आ० 1538.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स शकुन्तला पब्लिशिंग हाउस, मेकर भवन सं० 1, तीसरी मंजिल 1 न्यूमेरीन लाइन्स मुम्बई-20 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35018(21)/78-पी०एफ०-II]

S.O. 1538.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shakuntala Publishing House, Maker Bhavan No. 1, 2nd Floor 1 New Marine Lines, Bombay-20, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1977.

[No. S. 35018(12)/78-PF. II]

का०आ० 1539—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सिद्धेश्वर सहकारी सखर कारखाना लि०, मनिक नगर, तालुक-सिलोद जिला औरंगाबाद, नामक स्थापन से संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35018(28)/78-पी०एफ०-II]

S.O. 1539.—Whereas it apears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Sidheshwar Sahakari Sakhar Karkhana Limited Maniknagar, Sillod, District Aurangabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1977.

[No. S. 35018/28/78-PF.II]

का०आ० 1540.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आशीश टैक्सटाइल, आगरा रोड, पंचवटी, नासिक नामक स्थापन से संम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 फरवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं०एस० 35018(24)178-पी० एफ० II]

S.O. 1540.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ashish Textiles, Agra Road, Panchavati, Nasik-3, have been agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952, should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of February, 1977.

[No. S. 35018/24/78-PF. II]

का०आ० 1541—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आरती प्रोडक्ट्स आगरा रोड, पंचवटी, नासिक-3, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियमम की धारा 1 की उपधारा (4) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 फरवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35018(25)/78-पी०एफ०-II]

S.O. 1541.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Arti Products, Agra Road, Panchvati, Nasik-3, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of February, 1977.

[No. S. 35018/25/78-PF. II]

का०आ० 1542 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स माडर्पश एक्सपोर्टर्स (प्रा०) लिमिटेड, 97/99 अपोलो स्ट्रीट, मुम्बई समाचार मार्ग, फोर्ट, मुम्बई-23 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य अधिनियम और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थान को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 30 जून, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35018(26)/78-पी० एफ०-II]

S.O. 1542.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Modlash Exports (Private) Limited, 97/99, Apollo Street, Bombay Samachar Marg, Fort Bombay-23, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of June, 1977.

[No S. 35018(26)/78-PF. II]

का०आ० 1543 यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जीना सेल्स कारपोरेशन, शामशेट स्ट्रीट, मुम्बई-2, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 अक्टूबर, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं०एस० 35018(29)/78-पी०एफ० II]

S.O. 1543.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Jeena Sales Corporation, Shamshet Street, Bombay-2, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of October, 1975.

[No S. 35018(29)/78-PF. II]

का०आ० 1544—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इमेजियाड्स एण्ड कम्युनिकेशन्स (प्रा०) लिमिटेड, 103 मित्तल चेम्बर्स, 10वीं मंजिल नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-21 इसके अन्तर्गत (1) 24/6 लक्ष्मी रोड, 5वां क्रास शान्तिनगर, बंगलौर, 27 और (2) गौरी 1137/1 लायड्स रोड, मद्रास-14 स्थित इसकी शाखाएं भी हैं, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध के उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 अक्तूबर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(23)/78-पी०एफ० II]

S.O. 1544.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Imageads and Communications (Private) Limited, 103, Mittal Chambers, 10th Floor, Nariman Point, Bombay-21 including its branches at (1) 24/6, Lakshmi Road, 5th Cross, Shanthi Nagar, Bangalore-27 and (2) Gowri, 37/1 Lloyds Road, Madras-14, have agreed that the provisions of the Emvloyees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment;

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of October, 1976.

[No. S. 35018(23)/78-PF. II]

का०आ० 1545—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पोरिनियल प्रेस, सूर्यमहल, 5 बुर्जोराजी, भरोच मार्ग फोर्ट मुम्बई-23 इसमें नालन्दा बुक एण्ड रोड शाप शॉपिंग सेन्टर ताज इन्टर कान्टिनेन्टल होटल मुम्बई-39 स्थित इसकी शाखा भी है,

नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(27)/78-पी०एफ० II]

S.O. 1545.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Perennial Press, Surya Mahal, 5, Burjorji Bharucha Marg, Fort, Bombay-23 including its branch at Nalanda Book and Road Shop, Shopping Centre, Taj Intercontinental

Hotel, Bombay-39, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment;

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1977.

[No. S. 35019/27/78-PF. II]

का०आ० 1546.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इंजर्सोल रैन्ड (इण्डिया), लिमिटेड, 7 और 8 फेज-1 पीन्या औद्योगिक क्षेत्र, बंगलौर-58, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 6 जनवरी, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(40)/78-पी०एफ० II(i)]

S.O. 1546.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ingersoll Rand (India) Limited, 7 & 8 Phase-1, Peenya Industrial Area, Bangalore-58, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment;

This notification shall be deemed to have come into force on the sixth day of January, 1978.

[No. S. 35019(40)/78-PF. II(i)]

का०आ० 1547.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 6 जनवरी, 1978 से मैसर्स इंजर्सोल रैन्ड (इण्डिया) लिमिटेड, 7 और 8 फेज-1 पीन्या औद्योगिक क्षेत्र, बंगलौर-58, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस० 35019(40)/78-पी०एफ० II(ii)]

S.O. 1547.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the sixth day of January, 1978 the establishment known as Messrs Ingersoll Rand (India) Limited, 7 & 8 Phase-1, Peenya Industrial Area, Bangalore-58, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(40)/78-PF. II(ii)]

का०आ० 1548.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दि त्रिवेन्द्रम एक्स-सर्विसमैंस आटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग एण्ड ट्रान्सपोर्ट इण्डस्ट्रियल को-आपरेटिव सोसाइटी लि० नं० एस० आई० एन० डी० (टी) 256, पावर हाउस रोड, चेन्थिट्टा, त्रिवेन्द्रम-23, नामक स्थापन

से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(42)/78-पी०एफ०-2(i)]

S.O. 1548.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Trivandrum, Ex-servicemen's Automobiles Engineering and Transport Industrial Co-operative Society Limited, No. S. IND(T) 256, Power House Road, Chenthitta, Trivandrum-23, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment;

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of December, 1977.

[No. S. 35019(42)/78-PF. II(i)]

का०आ० 1549.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 दिसम्बर, 1977 से मैसर्स दि त्रिवेन्द्रम एक्स-सर्विसमैंस आटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग एण्ड ट्रांसपोर्ट इण्डस्ट्रियल को-आपरेटिव सोसाइटी लि०, सं० एस० आई० एन० डी० (टी) 256, पावर हाउस रोड, चेन्थिट्टा, त्रिवेन्द्रम-23 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस० 35019(42)/78-पी०एफ० 2(ii)]

S.O. 1549.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of December, 1977, the establishment known as Messrs The Trivandrum Ex-servicemen's Automobiles Engineering and Transport Industrial Co-operative Society Limited, No. S. IND(T) 256, Power House Road, Chenthitta, Trivandrum-23, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(42)/78-PF. II(ii)]

का०आ० 1550.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एस० कृष्णमूर्ति जूटवार्लिंग प्रेस, विजियानगरम्, जिला विशाखापटनम्, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(43)/78-पी०एफ० II]

S.O. 1550.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs S. Krishna Murty Jute-baling Press, Vizianagaram, Visakhapatnam District have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1977.

[No. S. 35019(43)/78-P. F. II]

का०आ० 1551.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स निशान फोर्ज (प्राइवेट) लिमिटेड, 1700, नेपियर टाउन, जबलपुर-1, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस० 35019(44)/78-पी०एफ० II(i)]

S.O. 1551.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Nissan Forge (Private) Limited, 1700, Napier Town, Jabalpur-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1977.

[No. S. 35019/44/78-PF. II(i)]

का०आ० 1552.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 जुलाई, 1977 से मैसर्स निशान फोर्ज (प्राइवेट) लिमिटेड, 1700, नेपियन टाउन, जबलपुर-1, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस० 35019(44)/78 पी०एफ० II(ii)]

S.O. 1552.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to Section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of July, 1977 the establishment known as Messrs Nissan Forge (Private) Limited, 1700, Napier Town, Jabalpur-1 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019/44/78-PF II(ii)]

का०आ० 1553.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स के०एल० प्लास्टिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड, 14, शिवाजी मार्ग, (नजफगढ़ रोड), नई दिल्ली-15 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत है की कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(50)/78-पी०एफ० II]

S.O. 1553.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs K. L. Plastics (Private) Limited, 14, Shivaji Marg, (Najafgarh Road), New Delhi-15, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1976.

[No. S. 35019(50)/78-PF. II]

का०आ० 1554.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स शिल्पी सेल्स, ए-22, नारायणा इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-2, नई दिल्ली-28 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(51)/78-पी०एफ० II]

S.O. 1554.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shilpi Sales, A-22, Naraina Industrial Area, Phase-II New Delhi-28, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1977.

[No. S. 35019/51/78-PF. II]

का०आ० 1555.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कोहिनूर लाजिंग एण्ड बोर्डिंग वापत बुरुड गली, बेलगाम, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती हैं।

यह अधिसूचना 1 फरवरी, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(52)/78-पी०एफ० II]

S.O. 1555.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kohinoor Lodging and Boarding Bapat Burud Galli, Belgaum, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of February, 1978.

[No. S. 35019(52)/78-PF. II]

का० आ० 1556.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसस सरित मैन्यूफैक्चरिंग एण्ड रिसर्च सेंटर, 5/3, बोरबैंक रोड, बंगलौर-46, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 फरवरी, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(57)/78-पी० एफ० II]

S.O. 1556.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sarit Manufacturing and Research Centre, 5/3, Borebank Road, Bangalore-46, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of February, 1978.

[No. S. 35019(57)/78-PF. II]

का० आ० 1557.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसस बी० कामराजू जूट बेलिंग प्रेस, विजियानगरम्-1, जिला विशाखापटनम्, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(58)/78-पी० एफ० II]

S.O. 1557.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs B. Kamaraju Jute Baling Press, Vizianagaram-1, Visakhapatnam District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1977.

[No. S-35019/58/78-PF. II]

का० आ० 1558.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अपलैंड्स गैस सर्विस, वाल्टेयर अपलैंड्स, विशाखापटनम्-3, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 मई, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(59)/78-पी० एफ० II]

S.O. 1558.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Uplands Gas Service, Waltair Uplands, Visakhapatnam-3 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1977.

[No. S-35019/59/78-PF. II]

का० आ० 1559.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मेजेस्टी वेंकटराजू एण्ड कम्पनी जूट बेलिंग प्रेस विजयानगरम्-1 जिला-विशाखापटनम, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(60)/78-पी० एफ० II]

S.O. 1559.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Majesty Venkata Raju and Company, Jute Baling Press, Vizianagaram-1, Visakhapatnam District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1977.

[No. S-35019(60)/78-PF. II]

का० आ० 1560.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पी० एस० के० फाइनेंस एण्ड चिट फण्ड्स लिमिटेड, सलेम-1, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 मई, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(61)/78-पी० एफ० II]

S.O. 1560.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs P. S. K. Finance and Chit Funds Limited, Salem-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1976.

[No. S-35019(61)/78-PF. II]

का० आ० 1561.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वीनस शूज एण्ड लेदर प्राडक्ट्स, रसूलगढ़, भुवनेश्वर-10, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 नवम्बर, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(62)/78-पी० एफ० II]

S.O. 1561.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Venus Shoes and Leather Products, Rasulagarh, Bhubaneswar-10, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1977.

[No. S-35019/62/78-PF. II]

का० आ० 1562.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स तीस-राउरकेला, उदित नगर, राउरकेला-769012, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(64)/78-पी० एफ० II(i)]

S.O. 1562.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Tis-Rourkela, Uditnagar, Rourkela-769012, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1977.

[No. S-35019(64)/78-PF. II(i)]

का० आ० 1563.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जाँच करने के पश्चात् 1 जनवरी, 1977 से मैसर्स तीस राउरकेला, उदितनगर, राउरकेला-769012 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35019(64)/78-पी० एफ० II (ii)]

S.O. 1563.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to Section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of January, 1977 the establishment known as Messrs Tis-Rourkela, Uditnagar, Rourkela-769012, for the purposes of the said proviso.

[No. S-35019(64)/78-PF. II(ii)]

का० आ० 1564.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री गजानन आटो रिपेयर्स, एम० टी० रोड, मंगलौर, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(72)/78-पी० एफ० II]

S.O. 1564.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sri Gajanana Auto Repairs, M. T. Road, Mangalore, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1977.

[No. S-35019(72)/78-PF. II]

का० आ० 1565 .—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ए० बी० सी० इंजीनियरिंग (प्राइवेट) लिमिटेड, विजय रोड धारवाड़ (कर्नाटक) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 सितम्बर, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एम० 35019(77)/78-पी० एफ० II (i)]

S.O. 1565.—Whreas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs A. B. C. Engineering (Private) Limtied, Vijaya Road, Dharwar (Karnataka), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1977.

[No. S-35019/77/78-PF. II(i)]

का० आ० 1566 —केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जाँच करने के पश्चात् 1 सितम्बर, 1977 से मैसर्स ए० बी० सी० इंजीनियरिंग (प्राइवेट) लिमिटेड, विजय रोड, धारवाड़ (कर्नाटक) नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35019 (77)/78-पी० एफ० II (ii)]

S.O. 1566.—In exercise of the powers conferred by the first proviso in Section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of September, 1977 the establishment known as Messrs A. B. C. Engineering (Private) Limited, Vijaya Road, Dharwar (Karnataka) for the purposes of the said proviso.

[No. S-35019/77/78-PF. II(ii)]

का० आ० 1567.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्रिन्टेड, शेड सं० 31, फेज 2 स्कीम-2, नव ओखला औद्योगिक कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-20 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एम० 35019(79)/78-पी० एफ० II]

S.O. 1567.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Printaid, Shed No. 31, Phase II, Scheme 2, New Okhla Industrial Complex, New Delhi-20, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1976.

[No. S. 35019/79/78-PF. II]

शुद्धि-पत्र

का० आ० 1568—भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 26 नवम्बर, 1977 के पृष्ठ 4078 पर प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3651 तारीख 26 नवम्बर, 1977 में पंक्ति 3, 4, और 5 में "मैसर्स मुन्नार सप्लाई एसोसिएशन लिमिटेड, मुन्नार पोस्ट आफिस, मुन्नार ग्राम, डेवीकोलमतालुक, इडिक्की जिला" के स्थान पर, "मैसर्स मुन्नार सप्लाई एसोसिएशन लिमिटेड, मुन्नार पोस्ट, मुन्नार ग्राम, डेवीकोलम तालुक, इडिक्की जिला" पढ़े ।

[सं० एस० 35019(381)/77-पी० एफ० II (i)]

CORRIGENDUM

S.O. 1568.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S. O. 3651, dated the 4th November, 1977 published at page 4078 of the Gazette of India Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 26th November, 1977 in lines 3, 4 and 5 for "Messrs Mannar Supply Association Limited, Mannar Post Office, Mannar Village, Devicolum Taluk, Idikki District", read "Messrs Munnar Supply Association Limited, Munnar Post, Munnar Village, Devicolam Taluk, Idikki District".

[No. S. 35019(381)/77-P.F. II(i)]

शुद्धि पत्र

का० आ० 1569 —भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 26 नवम्बर, 1977 के पृष्ठ 4078 पर प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3652 तारीख 4 नवम्बर, 1977 में पंक्ति 6, 7 और 8 में "मैसर्स मुन्नार सप्लाई एसोसिएशन लिमिटेड, मुन्नार पोस्ट आफिस मुन्नार ग्राम, डेवीकोलम तालुक, इडिक्की जिला" के स्थान पर, "मैसर्स मुन्नार सप्लाई एसोसिएशन लिमिटेड, मुन्नार पोस्ट, मुन्नार ग्राम, डेवीकोलम तालुक, इडिक्की जिला" पढ़े ।

[सं० एस० 35019(381)/77-पी० एफ० II (ii)]

CORRIGENDUM

S O. 1569.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 3652, dated the 4th November, 1977 published at page 4078 of the Gazette of India Part II Section 3, sub-section (ii) dated the 26th November, 1977 in lines 6, 7 and 8 for "Messrs Munnar Supply Association Limited Mannar Post Office, Munnar Village, Devicolum Taluk, Idikki District", read "Messrs Munnar Supply Association Limited, Munnar Post, Munnar Village, Devicolam Taluk, Idikki District".

[No. S. 35019(381)/77-PF. II(ii)]

नई दिल्ली, 16 मई, 1978

का० आ० 1570—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 28 मई, 1978 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्यायय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की उपधारा (1) और धारा

77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबन्ध उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"रायबरेली की नगरपालिका की सीमाओं तथा राजस्वग्राम बरखापुर, बालापुर, मलिकमाऊ, ऐमा, छालापुर, छाजलापुर, रट्ठापुर और धौरहारा परगना और तहसील बरखापुर, जिला रायबरेली के अन्तर्गत क्षेत्र।"

[सं० एस० 38013/6/78-एच०आई०]

New Delhi, the 16th May, 1978

S.O. 1570.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 28th May, 1978 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Uttar Pradesh, namely :—

The areas falling within the Municipal limits of Raibareilly and revenue villages of Barkhapur, Balapur, Malikmau, Aima, Chalapur, Chajlapur, Rattapur and Dhaurhara, Pargana and Tahsil Barkhapur, District Raibareilly.

[No. S. 38013/6/78-HI]

नई दिल्ली, 10 मई, 1978

का० आ० 1571.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 850 तारीख 10 मार्च, 1978 के क्रम में कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन को जो भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के अधीन पब्लिक सेक्टर उपक्रम है, उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 11 फरवरी, 1978 से 10 अगस्त, 1978 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, के लिए छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अवधि' कहा गया है), ऐसी विवरणियां, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ;

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख का, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं ; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं , या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के सम्बन्ध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं ;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है ; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के सन्दाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी परीक्षा करने दें, या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे वे आवश्यक समझते है ; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे पदधारण लेना ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है क्योंकि छूट के लिए प्राप्त आवेदन पत्र की कार्रवाई पर समय लगा । तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि कारखाना छूट का पात्र है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[सं० एच० 38014/19/76-एच० आई०]

एस० एस० सहस्रनामन, उप सचिव

New Delhi, the 10th May, 1978

S.O. 1571.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour No. S.O. 850 dated the 10th March, 1978, the Central Government after consultation with Employees' State Insurance Corporation hereby exempts the Cochin Shipyard Limited, Cochin a Public Sector Undertaking under the Ministry of Shipping and Transport from the operation of the said Act from the 11th February, 1978 upto and inclusive of the 10th August, 1978.

2. The above exemption is subject to the following condition, namely.

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations of 1950;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory

be empowered to—

(a) required the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found inchange thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal, or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such, factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interests of anybody adversely.

[No. S-38014/19/76-HI]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 मई, 1978

का० आ० 1572—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मेसर्स डालमिया मेग्नेसाइट कारपोरेशन, सलेम के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यदि केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री के० सत्यरत्नम होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा, तथा उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मेसर्स डालमिया मेग्नेसाइट कारपोरेशन, सलेम द्वारा अपने कर्मचारियों, श्रीमती कलियम्मा और श्रीमती पेरुमथी के अभिकथित अपचारों की जांच करवाए बिना, उपक्रम के प्रमाणित स्थायी आदेशों के खण्ड 28(घ) के उपबन्धों का आश्रय लेते हुए, उनकी सेवाओं को समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो, वे किस अनुतोष की हकदार हैं ?

[सं० एल०-29012/7/77-डी-III-बी०]

जगदीश प्रसाद, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th May, 1978

S.O. 1572.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Dalmia Magnesite Corporation, Salem and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (i) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri K. Selvarathnam shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Messrs Dalmia Magnesite Corporation, Salem, in terminating the services of Smt. Kaliamma and Smt. Perumayee, resorting to the provisions of Clause 28(d) of the certified standing orders of the undertaking, without holding an enquiry for the alleged misconducts of the employees is justified ? If not, to what relief are they entitled ?

[No. L-29012/7/77-D. III B.]

JAGDISH PRASAD, Under Secy.

S.O. 1573.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kessurgarh Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Nudkhurkee, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd May, 1978.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 3) AT DHANBAD

Reference No. 37 of 1976

In the matter of an industrial dispute under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Kessurgarh Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. P. O. Nudkhurkee, District Dhanbad

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers : Shri T. P. Choudhury, Advocate.

On behalf of the workmen : None.

STATE : BIHAR INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, 27th April, 1973.

AWARD

This is a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India, Ministry of Labour under order No. L-20012/26/76/DIIIA dated 26th June, 1976. The schedule is extracted below :

SCHEDULE

Whether the action of the management of Kessurgarh colliery of Messrs Bharat Coking Coal Ltd. Post

office Nudhkhurkee District Dhanbad in dismissing from service Shri Ramji Munda, Miner and Shri Babu Lal Bilaspuri, Hard Coke Stacker with effect from 30th August, 1975 is justified ? If not, to what relief are the workmen entitled ?

2. There was a conciliation proceeding which failed and then the Assistant Labour Commissioner (C) Dhanbad sent a failure report dated 30-1-75 to the Secretary to the Government of India, Ministry of Labour, New-Delhi.

3. Before the Conciliation Officer stand of the union was that the charge sheet was vague, notice of enquiry was not served upon Shri Ramji Munda, that Shri Babu Lal Bilaspuri was not given any opportunity to defend himself, the assaulted workman was not sent for medical examination, the enquiry officer was biased and past conduct was not at all considered and the punishment awarded was disproportionate to the alleged misconduct.

4. The management denied all the points raised by the union and reiterated that the enquiry was fair and proper and the gravity of misconduct was taken into account in awarding the punishment.

5. It may be mentioned that the two concerned workmen were dismissed from service with effect from 30th August, 1975. The union which sponsored the dispute is Koyala Mazdoor Union and the colliery involved is Kessurgarh under the management of M/s Bharat Coking Coal Limited.

7. Case of the union is that the charge sheet Ext. M-1 and M-2 were issued to Babu Lal Bilaspuri and Shri Ramji Munda respectively on 24-8-73 and the alleged misconduct was assault on Shri Sakaldeo Gope, Chaprasi at about 0.30 A.M. on 21-8-73 and for absenting from duty without permission and when Babu Lal returned to the colliery in August, 1974, copy of the charge-sheet was given to him and there was also an order of suspension. He submitted his reply, Ext. M-3, and he was allowed to resume his duty. Copy of the charge-sheet was served upon Shri Ramji Munda in October, 1974 and there was also an order of suspension. He sent his reply, Ext. M-4, and then he was allowed to resume his duty from 18th October, 1974.

8. It is said that this decision of the management to allow them to resume duty created a belief that they were inclined to accept their explanations. But in December, 1974 by a notice dated 29th December, 1974 enquiry was fixed at 9 A.M. on 2nd January, 1975 and the two workmen presented themselves but no enquiry was held. They were not informed of the adjourned date. This also created an impression that it was a formal notice for a formal enquiry to regularise few days of suspension as punishment for absence from duty.

9. It is submitted that about 7 months after an enquiry was held on 25th May, 1975 for which necessary intimation had not been given to them. Babu Lal was, however, available and he was made to take part and the enquiry was ex-parte so far as Ramji Munda was concerned.

10. It is contended that date of occurrence mentioned in the charge sheet is misleading and the place of occurrence is also not mentioned there. Sakaldeo Gope did not corroborate management's witnesses and statement of other witnesses is not reliable. The domestic enquiry violated the principles of natural justice and punishment of dismissal has been given on perverse finding.

11. It is submitted that the workmen are entitled to reinstatement with full back wages and other benefits.

12. In the written statement the management has taken a stand that the two concerned workmen jointly attacked Sakaldeo Gope in the midnight of 21/22-8-73 and caused grievous injury. Thereafter, they remained absent and a common charge-sheet was issued on 24th August, 1973 but it could not be served as their whereabouts were unknown. Subsequently, it transpired that they were detained in Dhanbad jail as under-trial prisoner.

13. It is further said that Babu Lal reported for duty in the beginning of August, 1974 and he was served with charge-sheet and an order of suspension pending enquiry. He replied to the charge-sheet on 3rd August, 1974 and was allowed to resume duty after some time. Ramji Munda reported for work in the middle of October, 1974 and he was served with the charge-sheet and an order of suspension pending enquiry. He replied on 15th October, 1974 and was allowed to resume duty after some time. A criminal case was pending against the concerned workmen in the Criminal Court at Dhanbad on the same charges and the management took some time to arrive at a decision to start a domestic enquiry. It was ultimately done and Shri B. B. Singh, Senior Personnel Officer, was appointed Enquiry Officer. Notices dated 22nd July, 1975 were issued and served on the concerned workmen by which enquiry was fixed on 25th July, 1975. Ext. M-5 is a peon book showing issue of that notice.

14. It is said that Babu Lal was present throughout the enquiry proceeding and Ramji Munda deliberately absented himself from the enquiry despite notice and it proceeded against him ex-parte. Witnesses examined on behalf of the management were offered for cross-examination by Babu Lal but he declined. He gave his own statement but did not produce any defence witness. The record of the enquiry proceeding is Ext. M-6 and the Enquiry Officer submitted his report, Ext. M-7 dated 4th August, 1975 holding the workmen guilty of the charges levelled. The General Manager, Area No. I, approved of the punishment of dismissal and the Agent thereupon issued dismissal letter dated 30th August, 1975 to the concerned workmen, which is Ext. M-10.

15. It is contended that the domestic enquiry was fair and proper and there was no element of unfair labour practice or victimisation. It is also said that the workmen are entitled to no relief.

16. From the record of the case it appears that nobody was present on behalf of the union on 31st May, 1977, 16th August, 1977, 11th October, 1977, 23rd November, 1977, 3rd January, 1978, 3rd April, 1978 as well as on 10th April, 1978. On the last date the case was taken up ex-parte and MW-1 was examined and he proved Exts. M-5 to M-10.

17. It seems that the union has lost interest in the case and has abandoned it. Therefore, it may be said to be a case of 'no dispute', but the management has examined a witness and brought certain records as exhibits to prove the fairness and propriety of the domestic enquiry and I propose to deal with the case. If I hold in favour of the enquiry the only question left will be the one under Section 11A of the Industrial Disputes Act and in the end it will be an award, of course, as I have said earlier of no dispute.

18. On behalf of the union a letter dated 29th December, 1974, Ext. W-1 has been brought on record wherein it is said that the explanation has been found unsatisfactory and there is a notice that the enquiry will commence on 2nd January, 1975 at 9 A.M. in the office of the manager and Shri B. B. Singh, Personnel Officer will be the Enquiry Officer. The enquiry, however, started on 25th July, 1975 as it will appear from Ext. M-6, the record of the enquiry proceeding. Ext. M-5 is the entry in the peon book dated 23rd July, 1975 by which notice for enquiry was sent to Shri Ramji Munda and he received it in his pen. Ext. W-1 had been produced with a view to show that originally the enquiry was to be conducted from 2nd January, 1975 but in fact it started on 25th July, 1975 for which the workmen had no notice. I have referred to the entry in the peon book, Ext. M-5 which shows that a letter dated 22nd July, 1975 was despatched on 23rd July, 1975 and it was received by Ramji Munda. It being a letter dated 22nd July, 1975 it can't be said that Ramji Munda had no information about the enquiry which was to commence from 25th July, 1975. So far as Babu Lal Bilaspuri is concerned there is a mention in Ext. M-6 that he was present and Ramji Munda is absent inspite of notice. It further shows that the Enquiry Officer read over and explained the charge-sheet and the reply thereto to Bilaspuri and he put his LTI. It is thus, clear that both the workmen had notice about the enquiry and while one attended it the other deliberately absented himself and if thereafter enquiry was conducted ex-parte against him, he can certainly have no grievance and even if any, that cannot be entertained.

19. The Enquiry Officer has stated that the witnesses for the management and the workmen himself were examined on 25th July, 1975 and he was given all possible opportunities to cross-examine witnesses for the management as well as to examine himself and to produce his own witnesses. He says further that he examined himself but declined to produce defence witnesses. Thereafter, he read over the recorded statements to the concerned workman who put his thumb

mark on each page and has proved Ext. M-6, Thereafter, he prepared his enquiry report, Ext. M-7.

20. If we refer to the record of the enquiry proceeding it will appear that on each page Babu Lal Bilaspuri has put his thumb impression and when asked to cross-examine he refused to cross-examine witness No. 1. The victim is Sakaldeo Gope, witness No. 2. He was examined in presence of the concerned workman and in cross-examination Babu Lal put one question. The 3rd witness and the rest were examined in his presence but he refused to cross-examine them. It appears that thereafter he examined himself and was cross-examined by Shri I. P. Choudhury, representative of the management. In his cross-examination he said that he knew that Ramji Munda had assaulted Sakaldeo Gope. Thereafter, he declined to give defence witness.

21. From the above it would appear that every opportunity was given to Bilaspuri to participate in the enquiry, to cross-examine witnesses for the management, to examine himself and to produce his witnesses. Undoubtedly, therefore, the Enquiry officer proceeded in a very fair way and it appears without any bias against him.

22. So far as Ramji Munda is concerned in spite of notice he absented himself and the Enquiry Officer was justified in proceeding ex parte against him.

23. If we refer to the charge-sheets, Exts. M-1 and M-2 we will find that it gives the details of the charge and the relevant clause of Standing Orders is also mentioned therein. Enquiry was started because the explanations were found unsatisfactory and Exts. M-3 and M-4 will amply support this conclusion. I have already said above that there was notice to the concerned workmen for the enquiry. Therefore, the allegation that the charge-sheet is vague is not sustainable and in their written statement the management has given cogent reason why enquiry was started so late after the occurance. On the consideration of all the available materials I am of opinion that the enquiry was fair and proper and the principles of natural justice had been adhered to. There is no material for a conclusion that it was an act of unfair labour practice or that the concerned workmen were victimised for their trade union activities. That brings us to the question of the quantum of punishment.

24. Witnesses who were examined before the Enquiry Officer consistently stated that Sakaldeo Gope was assaulted by the two concerned workmen. This has been testified to by Sukdip Gope and has been supported by Dulal Chandra Gope, Ram Charitar Gope, Ram Prabash Gope, who are all eye witnesses to the occurance. Enquiry Officer was therefore, justified in holding the concerned workmen guilty of misconduct mentioned in the charge-sheet. Being in jail for a considerable long time they were certainly absent from duty without permission. On the materials available before the Enquiry Officer no other conclusion could have been possible and if on the same materials the two concerned workmen have been dismissed for grave misconduct, it cannot be said that the punishment is disproportionate to the act of misconduct committed by them.

25. The enquiry report was perused and considered by the Manager and he made his notes, Ext. M-8 and forwarded it to the Agent who also examined the materials and recommended for dismissal as it would appear from his note, Ext. M-9. The General Manager, thereafter issued the letter of dismissal, Ext. M-10. It means that the finding of the Enquiry Officer was considered by all the concerned authorities and when they were satisfied that the charge of misconduct had been proved against the two concerned workmen, the order of dismissal was passed.

26. It would thus appear that the enquiry had been fair and proper, the conclusion of the Enquiry Officer is supported by the materials on record and the order of dismissal could have been the only possible punishment for the grave act of misconduct committed by the concerned workmen. The worst type of violence that was committed caused grevious injury to a co-worker. I do not think there is any extenuating circumstance to disagree with the order of dismissal.

27. The management of Kessurgarh colliery was justified in dismissing from service Shri Ramji Munda, Miner and Shri Babu Lal Bilaspuri, Hard Coke Stacker, with effect from 30th August, 1975 and the two workmen are entitled to no relief.

This is my award.

S. R. SINHA, Presiding Officer

[No. L-20012/26/76-D.III(A)]

S. H. S. IYER, Desk Officer

नई दिल्ली, 10 मई 1978

का० आ० 1574.—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की समाप्ति पर या उसके पश्चात् उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा ।

दो मास की उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत किसी भी व्यक्ति से जो भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी ।

अधिसूचना का प्रारूप

केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट के अधीन मोटर पाइलट यान "वेनू" में नियोजित कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के संबंध में प्रवृत्त विशेष विनियमों का ध्यान रखते हुए, यह निदेश देती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होने वाली दो वर्ष की अवधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 और 14 के उपबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उन कर्मचारियों को लागू नहीं होंगे, अर्थात् :—

(1) मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट, विनियम एक पुस्तिका के रूप में अंग्रेजी भाषा या बहुसंख्यक कर्मचारियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा या भाषाओं में प्रकाशित किए जाएंगे ;

(2) मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट, पूर्वोक्त विनियमों में कोई संशोधन करने से पूर्व प्रस्तावित संशोधनों की सूचना सम्बद्ध कर्मचारियों को देगा जो पूर्वोक्त पोर्ट ट्रस्ट के कार्यालय के सूचना पटल पर लगाई जाएगी और वह ऐसे किसी भी आक्षेप या सुझाव पर विचार करेगा जो ऐसी सूचना के इक्कीस दिन के भीतर उसके संबंध में किए जाएंगे ; और

(3) खण्ड (1) में निर्दिष्ट पुस्तिका की एक प्रति और उसके प्रत्येक संशोधन की एक प्रति प्रत्येक सम्बद्ध कर्मचारी को दी जाएगी ।

[सं० एस० 32014(1)78-डब्ल्यू० सी० (एम० डब्ल्यू०)]

हंस राज छाबड़ा, उप सचिव

New Delhi, the 10th May, 1978

S.O. 1574.—The following draft of a notification which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft before the expiry of the said period of two months will be considered by the Central Government.

DRAFT NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government having regard to the special

regulations in force in respect of the service conditions of the employees working in the Motor Pilot Vessel "Venu" under the Bombay Port Trust, hereby directs that the provisions of Sections 13 and 14 of the said Act shall not apply to those employees for a period of two years commencing from the date of publication of this notification in the Official Gazette, subject to the following conditions, namely :—

(i) the Bombay Port Trust shall publish the regulations in a pamphlet form in the English language and in the language or languages understood by the majority of the employees.

(ii) before making any amendment to the aforesaid regulations, the Bombay Port Trust shall inform the employees concerned by notice, to be put up on the notice board, at the office of the aforesaid Port Trust, of the proposed amendments and shall consider any objections or suggestions that may be made thereto within twenty-one days of such notice ; and

(iii) a copy of the pamphlet referred to in clause (i) and a copy of every amendment thereto shall be supplied to each employee concerned.

[No. S-32014(1)/78-WC(MW)]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

आदेश

का० आ० 1575.—इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में पंजाब नैशनल बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं० 1, धनबाद के समक्ष लम्बित है जिसके पीठासीन अधिकारी स्वर्गीय श्री के० बी० श्रीवास्तव थे ।

और श्री के० बी० श्रीवास्तव की सेवाएं अब उपलब्ध नहीं है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद से सम्बद्ध कार्यवाही को केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं० 1 धनबाद से वापस लेती है और उसे उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं० 3, धनबाद को इस निदेश के साथ स्थानान्तरित करती है कि उक्त केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं० 3, धनबाद और आगे कार्यवाही उसी प्रक्रम से करेगा जिस पर वह उसे स्थानान्तरित की जाये और विधि के अनुसार उसका निपटान करेगा ।

अनुसूची

"क्या पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्धतंत्र की बैंक के शाखा कार्यालय, जहानाबाद के अधीन तेहटा के लिपिक एवं गोदाम रक्षक श्री जो० एन० दास को स्थायी न मानने और उनकी सेवा को 26-8-1974 से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित श्रमिक किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल—12012(85)/75-डी-2ए]

आर० पी० नरूला, अवर सचिव

ORDER

S.O. 1575.—Whereas the industrial dispute existing between the employers in relation to the Punjab National Bank and their workman in respect of the matters specified in the schedule hereto annexed is pending before the Central Government Industrial Tribunal, No. I Dhanbad presided over by the late Shri K. B. Srivastava ;

And whereas the services of Shri K. B. Srivastava are no longer available ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33B of Industrial Disputes Act, 1947 the Central Government hereby withdraws the proceedings in relation to the said dispute from the Central Government Industrial Tribunal, No. I Dhanbad and transfer the same to the Central Government Industrial Tribunal, No. III Dhanbad constituted under section 7A of the said Act and directs that the said Central Government Industrial Tribunal, No. III Dhanbad shall proceed with the same proceedings from the stage at which they are transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of the Punjab National Bank in not treating Shri G. L. Das, Clerk-cum-Godown Keeper at Tehta under its Branch Office, Jehanabad as confirmed and in terminating his services with effect from 26th August, 1974 is justified ? If not to what relief is the said workman entitled ?"

[F. No. L-12012/85/75-D.II.A]

R. P. NARULA, Under Secy.

S.O. 1576.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Delhi, Delhi, in the industrial dispute between the employers in relation to the Management of M/s. Birla Cement Works, Birla Works Cement Lime Stone Quarries, Chittorgarh and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd May, 1978.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

I.D. No. 21 of 1977

BETWEEN

The President, Cement Factory Mazdoor Sangh, 24, Residency Road, Chittorgarh—Petitioner.

Versus

M/s. Birla Cement Works, Birla Works Cement Lime Stone Quarries, Chittogarh.—Respondent.

PRESENT :

Shri Prem Kishan—for the workman with the workman.

Shri R. C. Vyas—for the Management.

AWARD

The Central Govt. as appropriate Govt. vide its order No. L. 29011/37/76-D. IIIB dated the 22nd February, 1977 made a reference u/s 10 of the I.D. Act, 1947 to this Tribunal in the following terms :

"Whether the action of M/s. Birla Cement Works, owners of Birla Cement Lime Stone Quarries, Chittorgarh in suspending Shri Mangi Lal, Dumper Operator w.e.f. 22-1-1974 and subsequently dismissing from service was justified ? If not, to what relief is he entitled ?"

2. After the reference was registered usual notices were sent to the parties and a statement of claim was filed on behalf of the workman. A written statement thereafter was filed. Before any further proceedings could be held the parties have arrived at a settlement and have filed the said settlement Ex. S-1 in the court. I have perused the settlement and found that the settltment was for the benefit of the workman and accordingly it was ordered to be recorded and registered. The statement of Shri Mangi Lal, the workman and Shri Prem Kishan for the Union and Shri R. C. Vyas for the Management was recorded vide my order dated the 25th February, 1978. The said statements reads as follows :

"The parties have settled the dispute vide settlement Ex. S/1. The settlement may be recorded and award be made in terms of the settlement".

3. Accordingly an award in terms of the settlement Ex. S-1 is hereby made. The settlement Ex. S/1 would

form part of this award. The parties be left to bear their own costs.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer.

Dated: the 4th March, 1978.

MEMORANDUM OF SETTLEMENT

Name of Parties: Birla Cement Works Limestone Mines, Chittorgarh.

AND

Shri Mangilal, Workman concerned.

Representing the Management : Shri M. M. Goswami, Agent of the Mines.

Representing Workman : Shri Mangilal (Workman himself).

SHORT RECITAL OF THE CASE

That Shri Mangilal Jethi (hereinafter called workman) was employed as a dumper driver in Birla Cement Works Limestone Mines (which is a mine of Birla Cement Works, Chitorgarh) (hereinafter referred to as Mines).

2. That the services of Shri Mangilal were terminated vide letter of the management dated 24th June, 1974 after his having been found guilty in the domestic enquiry which was instituted against him regarding the chargesheet served to him on 25th January, 1974.

3. On aggrieved, the workman along with others raised a dispute which was referred by the Govt. of Rajasthan to the Labour Court, Rajasthan. The Hon'ble Labour Court rejected the reference as the State Govt. was incompetent to make the said reference since the appropriate Govt. in his case was the Central Govt. The said Shri Mangilal again raised a dispute which was taken in conciliation by the Assistant Labour Commissioner (Central) Kota. As the conciliation failed, the Central Govt. vide its order No. L-29011/37/76-D III B dated 22nd February, 1977 referred the dispute regarding the termination of the said Shri Mangilal to the Central Govt. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, New Delhi. The said reference was registered by the Hon'ble Tribunal as Case No. 21/1977 which is pending adjudication.

4. That the said Shri Mangilal approached the company for an amicable and out of court settlement of the dispute as he is already gainfully employed with M/s. Rajasthan State Mines & Minerals Ltd. Udaipur. Hence negotiations were held between the parties. The dispute has been fully and finally settled on the following terms and conditions :—

(a) That the said Shri Mangilal accepts the order of termination dated 24th June, 1974 and it is agreed that the said Shri Mangilal shall not pursue and or contest the said order of reference which is pending adjudication before the Central Govt. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, New Delhi as Case No. 21/1977.

(b) That it is agreed to by the management that in consideration of Shri Mangilal having accepted the order of termination, it shall pay lump sum amount of Rs. 10000 (Rs. Ten thousand only) in full and final settlement of the dispute. The lump sum amount of Rs. 10000 which will be paid to him includes the gratuity (payable under the Payment of Gratuity Act) for his past services and any other legal dues payable to him.

(c) That it is further agreed to by the said Shri Mangilal that hereafter, he shall have no financial claims like wages for the period of his idleness, bonus, leave or any other contributory fund, gratuity etc. and shall have no claims for reinstatement/reemployment against the company.

(d) That it is agreed to by and between the parties that the settlement shall be filed by the management on behalf of parties to this settlement before Shri Mahesh Chandra, Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, New Delhi in the matter of Case No. 21/77 with a prayer on behalf of the parties to this settlement to pass an award in terms of this settlement.

(e) That it is agreed to that the payment of lump-sum amount of Rs. Ten thousand only as agreed to in Para 4(b) shall be paid to Shri Mangilal within seven days after passing of the appropriate order by the Hon'ble Judge of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, New Delhi and after submission of 'no dues clearance certificate' from the concerned department and handing over of the vacant possession of company's quarter No. F-5/1 which is still in his possession.

(f) That it is agreed to by the management that after handing over of the vacant possession of company's quarter No. F-5/1, the management shall move an appropriate petition for the withdrawal of suit No. 14/74 pending before the Chief Judicial Magistrate, Chittorgarh.

(g) That it is agreed to that Shri Mangilal hereafter shall have no claims monetary or otherwise arising out of his termination of service by the company and or arising out of his part services rendered by him.

(h) That it is agreed to by and between the parties that the subject matter of the present dispute regarding termination of the services of Shri Mangilal stands completely resolved in consideration of the terms of this settlement which are full and final settlement of all his claims, demands, dues whatsoever in the matter of his claim for reinstatement, backwages etc. including any claim for any financial benefit whatever after the termination of his services and also with regard to his past services.

(i) That this settlement is signed by and between the parties on this day of 25th February, 1978 at Jaipur.

For & on behalf of

Birla Cement Works Limestone Mines,

Chittorgarh (Birla Cement Works).

Agent & Vice President

For & on behalf of Workman

Mangilal

Witnesses :

1. Surendra Singh BCW, Jaipur.
2. M. L. Baraya, R.C.D., Jaipur.

[No. L-29011/37/76-D. III. B.]

New Delhi, the 20th May, 1978

S.O. 1577.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal Gujarat Ahmedabad, in the industrial dispute between the employers in relation to the Management of Oil & Natural Gas Commission and their workmen which was received by the Central Government on the 4th May, 1978.

BEFORE SHRI R. C. ISRANI, PRESIDING OFFICER,

INDUSTRIAL TRIBUNAL, AHMEDABAD

Reference (ITC) No. 8 of 1976

ADJUDICATION

BETWEEN

The Oil & Natural Gas Commission, Baroda

AND

The Workmen employed under it.

In the matter of Pay, H.R.A., etc.

AWARD

This is a reference made by the Government of India, vide Ministry of Labour's Order No. L-30011(4)/76-D-IV(B), dated the 19th October, 1976, under clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, in respect of an industrial dispute which has arisen between the

parties, viz. the Oil & Natural Gas Commission, Baroda, and the workmen employed under it. The reference was at first made to the Industrial Tribunal consisting of Shri M. U. Shah, but thereafter, (vide the Government of India (Ministry of Labour) No. 5-11025(7)77-D-IV(B), dated 27-8-1977, the reference has been transferred to this Tribunal.

The dispute, as it appears from the schedule attached to the original order, under which this reference has been made, is to the following effect :

"(i) Whether the management of Oil and Natural Gas Commission, Baroda was justified in not paying allowance for the period from 4-9-1962 to 9-10-1966 and house rent allowance for the period from 1-9-1962 to 20-6-1965 to the employees employed in Technical Training Institute, NOGC, Baroda ? If not, to what relief are the said workmen entitled ?

(ii) Whether the management was justified in making recovery of House Rent for commission's accommodation at the rate of 10 per cent instead of 5 per cent for the period from 1-6-1964 to 4-12-1966 in respect of the employees employed in Technical Training Institute, ONGC, Baroda ? If not, to what relief are the said workmen entitled ?"

Before this reference could be heard on its merits and finally decided it is gratifying to note that the parties have arrived at an amicable settlement, the terms of which are recorded at Ex. 5. It is prayed by the parties that the award in this reference be made in terms of that settlement. This settlement is signed on behalf of the first party by a representative of the management, Shri M. B. Patel. On behalf of the workmen, it is signed by the general secretary of the ONGC, E.M.S., Baroda. I have examined the terms of this settlement, and have also scrutinized them against the background of the demands covered by this reference. On such scrutiny, I am of the opinion that the settlement is quite just and fair and it is also in the interest of the workmen covered by this reference. There would, therefore, be no difficulty in recording that settlement.

It is, therefore, hereby directed that the award in this reference, be made in terms of the settlement (Ex. 5), which is appended hereto as Annexure 'A'.

R. C. ISRANI, Presiding Officer.

Dated : 15th April 1978.

ANNEXURE 'A'

Reference CITC 8/76

BEFORE SHRI R. C. ISRANI, PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, AHMEDABAD

BETWEEN

The Workmen
represented through
ONGC Employees Mazdoor Sabha
Baroda. ....Applicant.

AND

Oil and Natural Gas Commission,
Makarpura Road,
Baroda-9. ... Opponent.

In the Matter of Payment of Drilling Allowance THRA etc. to T.T.I. Employees

The following disputes relating to the staff of Technical Training Institute, ONGC, Cambay has been referred to for adjudication by the Central Government vide their order No. L-30011(4)/76-D-IV(B) dt. 19-10-76.

(i) Whether the management of Oil and Natural Gas Commission, Baroda was justified in not paying allowance for the period from 4-9-1962 to 9-10-1966 and house rent allowance for the period from 1-9-1962 to 20-6-1965 to the employees employed in Technical Training Institute, ONGC, Cambay. If not, to what relief are the said workmen entitled ?

(ii) Whether the management was justified in making recovery of House Rent for the Commission's accommodation at the rate of 10 per cent instead of 5 per cent for period from 1-6-1964 to 4-12-1966 in respect of the employees employed in Technical Training Institute, ONGC, Baroda ? If not, to what relief are the said workmen entitled ?

The above dispute is presently pending before this Honourable Court.

In order to maintin cordial relations between the management and its workmen, both the parties without going into the merits of the case hereby agree as under :—

Terms of Settlement

1. The Commission' shall pay to its employees employed in Technical Training Institute, ONGC, Cambay during the relevant periods an amount equivalent to 70 per cent of the amounts claimed by them through this demand.

The calculation of the amounts shall be subject to verification by the concerned Accounts and Finance Officer of the ONGC and the employees shall receive this payment in full and final settlement of their claim and thereafter no claim of whatsoever nature relating to above disputes for the aforesaid period shall survive.

The Honourable Court be pleased to give its ward in terms of the above settlement.

Sd/- (Illegible)
Representative of Management
Sd/- (Illegible)
Representative of Workmen.
Gen. Secretary, ONGC,
E.M.S., Baroda.

Witness

[No. L-30011/4/76-DIVB/D III B]

JAGDISH PRASAD, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978